Kamal.Sandesh kamalsandesh.org KamalSandesh

कमल संदेश

वर्ष-20, अंक-18 16-30 सितम्बर, 2025 (पाक्षिक) ₹20

सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025

#NextGenGST

'राष्ट्र जीएसटी व्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता है'

जबलपुर (मध्य प्रदेश) में 25 अगस्त, 2025 को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

मुंबई में 31 अगस्त, 2025 को 'मन की बात' कार्यक्रम सुनते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े एवं पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेतागण

नई दिल्ली में 03 सितंबर, 2025 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम श्री लॉरेंस वोंग के साथ बातचीत करते भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा

असम में 29 अगस्त, 2025 को 'एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन' में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का स्वागत करते असम भाजपा के नेतागण

जम्मू में 01 सितंबर, 2025 को प्रदेश में आई हालिया बाढ़ की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता करते केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह

जोधपुर (राजस्थान) में 25 अगस्त, 2025 को आदर्श रक्षा एवं खेल अकादमी का उद्घाटन करते रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत

कमल संदेश

पाक्षिक पत्रिका

संपादक
डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सह संपादक
संजीव कुमार सिन्हा
राम नयन सिंह

कला संपादक
विकास सैनी
भोला राय

डिजिटल मीडिया
राजीव कुमार
विपुल शर्मा

सदस्यता एवं वितरण
सतीश कुमार

इ-मेल
mail.kamalsandesh@gmail.com
mail@kamalsandesh.com
फोन: 011-23381428, फैक्स: 011-23387887
वेबसाइट: www.kamalsandesh.org

विषय-सूची

06 **आम आदमी को भारी राहत, व्यवसायों को बढ़ावा और अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व तेजी**
केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद् ने तीन सितंबर को अब अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों...

12 सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली
श्री चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर, 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति...

15 देश के लिए कांग्रेस अमावस्या है, तो भाजपा पूर्णमासी की तरह है : जगत प्रकाश नड्डा
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा...

17 एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन, गुवाहाटी (असम)
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 अगस्त, 2025 को असम के अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे और अंतिम दिन...

22 प्रधानमंत्री तियानजिन (चीन) में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 तक चीन के...

लेख

मोहन भागवत जी: 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के प्रबल समर्थक / **नरेन्द्र मोदी** 20

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना युवा शक्ति के सपनों को देगी नई उड़ान / **डॉ. मनसुख मांडविया** 26

जीएसटी कटौती 2025: मजबूत विकास के लिए जन-केंद्रित सुधार / **अरुण सिंह** 28

भारत का दर्द, भारत का संकल्प / **तरुण चुग** 30

श्रद्धांजलि

राष्ट्र जीवन की समस्याएं / **पं. दीनदयाल उपाध्याय** 18

अन्य

'स्पेस से लेकर स्टार्टअप्स तक भारतीय युवाओं का डंका सारी दुनिया में बज रहा है' 16

प्रधानमंत्री ने 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान की यात्रा की 24

अप्रैल-जून, 2025 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की हुई भारी वृद्धि 25

पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने को मिली मंजूरी 25

'मन की बात' 32

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुंबई में सुनी 'मन की बात' 33

'भाजपा को जानें' पहल 34

प्रकाशक एवं मुद्रक: डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास के लिए विष्णु मित्तल द्वारा मुद्रित एवं प्रकाशित, एच.टी. मीडिया लिमिटेड, प्लॉट नं.-8, उद्योग विहार, ग्रेटर नोएडा (उ.प्र.)-201306 से मुद्रित एवं डॉ. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी.-66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली-110003 से प्रकाशित। संपादक- डॉ. शिव शक्ति नाथ बक्सी

सोशल मीडिया से

नरेन्द्र मोदी

आरजेडी जैसे दल कभी महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। इसलिए जब एक गरीब घर की माताएं-बहनें आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती हैं, तो वे बहुत बौखला जाते हैं।

(02 सितंबर, 2025)

जगत प्रकाश नड्डा

कांग्रेस की तथाकथित वोट अधिकार यात्रा में जिस तरह से कांग्रेस-आरजेडी के मंच से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की दिवंगत माता जी को गाली दी गई, वह घोर निंदनीय और भर्त्सनीय है। यह अभद्रता की सारी सीमा लांघ चुके दो शहजादों का बिहार की धरती पर बिहार की संस्कृति का तिरस्कार भी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को इस कुकृत्य के लिए अविलंब माफी मांगनी चाहिए। (28 अगस्त, 2025)

अमित शाह

बिहार में चल रही 'घुसपैठिया बचाओ यात्रा' में मोदीजी और उनकी स्वर्गीय माताजी के लिए कहे गए अपशब्द, राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई निम्न स्तर की नकारात्मक राजनीति का प्रतीक है।

(29 अगस्त, 2025)

राजनाथ सिंह

आज रक्षा क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को सशक्त और सुरक्षित रखने वाला प्रमुख स्तंभ बन चुका है। यह केवल सीमाओं की रक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी अर्थव्यवस्था के संरक्षण की भी जिम्मेदारी निभा रहा है।

(30 अगस्त, 2025)

बी.एल. संतोष

थिरु सीपी राधाकृष्णन को 767 में से 452 मतों के साथ भारत का उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। अपने दीर्घकालिक सामाजिक जीवन में उन्होंने जिस सौम्यता के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है, वह उनकी नई ज़िम्मेदारी में भी परिलक्षित होगा।

(9 सितंबर, 2025)

मनोहर लाल

गुरुग्राम मेट्रो विस्तार परियोजना केवल यातायात सुविधा का विस्तार नहीं बल्कि गुरुग्राम के समग्र विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इससे शहर की आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक प्रगति को नई गति मिलेगी।

(5 सितंबर, 2025)

संपादकीय

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार
राष्ट्र को सशक्त बनाने वाली जन-हितैषी पहल

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लागू होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 11 वर्षों की अभूतपूर्व उपलब्धियों से प्राप्त 'आत्मविश्वास' और 'मजबूती' के बल पर परिवर्तन के एक नए युग में प्रवेश कर रही है। यह वास्तव में दीपावली का बड़ा उपहार है, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से की थी। बीते 11 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक सुधार लागू किए गए, जिनके परिणामस्वरूप भारत ने 'फ्रेज़ाइल फाइव' से 'टॉप फाइव' तक की अद्भुत यात्रा तय की है। आज पूरी दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को स्वीकार कर रही है और निराशाजनक वैश्विक आर्थिक परिदृश्य के बीच यह सबसे चमकते सितारे के रूप में उभरा हैं।

विभिन्न अग्रणी सुधारों में 'जीएसटी' को एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, जिसने 'एक राष्ट्र, एक कर' के मंत्र के अंतर्गत भारतीय अर्थव्यवस्था के एकीकरण के सपने को साकार किया है। आयकर में बड़ी राहत के तुरंत बाद लागू किए गए जीएसटी सुधार का सकारात्मक प्रभाव एक नई करदाता-अनुकूल व्यवस्था के रूप में सामने आया है, जिसमें अनुपालन की लागत घटी है और देश की वित्तीय स्थिति और सुदृढ़ हुई है। जीएसटी ने अर्थव्यवस्था में गहरे बदलाव किए हैं- मुद्रास्फीति में कमी, जीडीपी विकास दर में वृद्धि, मांग में तेजी और दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। साथ ही, आम लोगों के लिए कर भार में कमी इसे एक विशेष जन-हितैषी पहल बनाती है। संक्षेप में, जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाकर राष्ट्र को सशक्त किया है और भारत की आर्थिक यात्रा को नई गति प्रदान की है।

> **अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के लागू होने के साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था पिछले 11 वर्षों की अभूतपूर्व उपलब्धियों से प्राप्त 'आत्मविश्वास' और 'मजबूती' के बल पर परिवर्तन के एक नए युग में प्रवेश कर रही है**

जीएसटी परिषद् ने अपनी 56वीं बैठक में दर संरचनाओं और प्रक्रियाओं में व्यापक संशोधनों को मंज़ूरी दी है। इसके साथ ही, जीएसटी की दर संरचनाएं मौजूदा चार स्लैब से घटकर दो पर आ गई हैं, जिनकी नई दरें क्रमशः 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत निर्धारित की गई हैं। यह कदम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के उस दृष्टिकोण से प्रेरित है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लागू करके आम आदमी पर कर का बोझ कम करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। इन सुधारों का मूल उद्देश्य है- 'जीवन को आसान बनाना' और जन-केंद्रित दृष्टिकोण के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को और मजबूत करना है।

इन परिवर्तनों से सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशा है। वस्तुओं और सेवाओं की नई जीएसटी दरें 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगी। यह कदम अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को और अधिक सरल, पारदर्शी और कुशल बनाने की दिशा में परिवर्तनकारी सिद्ध होगा। नई व्यवस्था में आवश्यक दैनिक वस्तुओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे क्षेत्रों पर कर का बोझ उल्लेखनीय रूप से कम होगा, जिससे जीवनयापन की लागत घटेगी। सुव्यवस्थित अनुपालन प्रक्रियाएं, स्वचालित पंजीकरण और त्वरित रिफंड व्यवस्था विशेष रूप से एमएसएमई और छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाएंगी। ये सुधार न केवल परिवारों और उद्यमों पर बोझ कम करेंगे, बल्कि भारत की विकास यात्रा को और अधिक गति देंगे। समावेशी उपायों और राजकोषीय विवेकशीलता का संतुलन बनाते हुए यह कदम एक सरल, अधिक कुशल और जन-हितैषी जीएसटी व्यवस्था के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में ऐतिहासिक उपलब्धि है।

आज भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। वित्त वर्ष 2026 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.8 प्रतिशत दर्ज की गई, जो न केवल पिछली पांच तिमाहियों में सबसे तेज वृद्धि है बल्कि अर्थशास्त्रियों के 6.5–6.7 प्रतिशत के अनुमानों से कहीं अधिक है।

फिच रेटिंग्स, आईएमएफ, ओईसीडी, एशियाई विकास बैंक, विश्व बैंक, मॉर्गन स्टेनली और क्रिसिल जैसी अग्रणी वैश्विक एजेंसियों ने भारत की अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक सकारात्मक टिप्पणियां करते हुए अपने आकलनों को पहले से बेहतर किया है। जब 2025 में वैश्विक विकास दर मात्र 3.0 प्रतिशत रहने का अनुमान है, तब भारत की 6.4 प्रतिशत से अधिक की विकास दर हमारे असाधारण लचीलेपन और मजबूती को रेखांकित करती है। अनुमानों के अनुसार, 2028 तक वैश्विक आर्थिक विकास में भारत का योगदान 20 प्रतिशत तक पहुंच जाएगा; यह हमारी विश्व अर्थव्यवस्था में बढ़ती केंद्रीय भूमिका का स्पष्ट संकेत है। यही कारण है कि अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का कार्यान्वयन एक ऐतिहासिक नीतिगत मील का पत्थर माना जा रहा है। यह सुधार खपत को बढ़ावा देने, कर व्यवस्था को सरल बनाने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने की दिशा में निर्णायक कदम है। निस्संदेह, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार भारत की आर्थिक यात्रा को नई गति प्रदान करेंगे और हमें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ऐतिहासिक छलांग के लिए तैयार करेंगे। ■

shivshaktibakshi@kamalsandesh.org

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025

आम आदमी को भारी राहत, व्यवसायों को बढ़ावा और अर्थव्यवस्था में अभूतपूर्व तेजी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले की प्राचीर से अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री के इस संकल्प को सिद्धि में बदलते हुए जीएसटी परिषद् ने तीन सितंबर को अपनी 56वीं बैठक में आम जन के जीवन को बेहतर बनाने, छोटे व्यापारियों-कारिबारियों समेत सभी के लिए 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' सुनिश्चित करने हेतु बहु-क्षेत्रीय व बहु-विषयक सुधारों को मंजूरी दी। इन सुधारों ने मौजूदा 4 स्तरीय टैक्स रेट ढांचे को 'सिंपल टैक्स' में बदल दिया, जिसमें 2 दर संरचनाएं— 18% का स्टैंडर्ड रेट और 5% का मेरिट रेट हैं तथा कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% का विशेष डिमेरिट रेट है। ये संशोधित दरें और छूट 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी। आम आदमी की कई वस्तुएं जैसे हेयर ऑयल, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, साइकिल आदि पर जीएसटी 18% या 12% से घटाकर 5% तथा लगभग सभी खाद्य पदार्थों जैसे पैकेज्ड नमकीन, भुजिया, कॉर्नफ्लेक्स, मक्खन, घी आदि पर जीएसटी 12% या 18% से घटाकर 5%; बहुत अधिक तापमान वाला (यूएचटी) दूध, पहले से पैक और लेबल वाला छेना या पनीर पर जीएसटी 5% से घटाकर शून्य तथा चपाती, पराठा, परोटा आदि पर जीएसटी हटा दिया गया। 33 जीवनरक्षक दवाओं और औषधियों पर जीएसटी 12% से घटाकर शून्य और सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। कृषि वस्तुओं, ट्रैक्टर, कटाई या थ्रेसिंग मशीनरी आदि पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया गया। एयर कंडीशनिंग मशीन, 32 इंच के टीवी (सभी टीवी पर अब 18% कर), छोटी कार, 350 सीसी या उससे कम क्षमता वाली मोटरसाइकिल पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि स्वतंत्रता के बाद से भारत का सबसे महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर सुधार 'जीएसटी' को औपचारिक रूप से 1 जुलाई, 2017 की आधी रात को लागू किया गया था, जिसमें 17 अलग-अलग करों और 13 उपकरों को एक 'समेकित कर' में समाहित कर दिया गया। फलस्वरूप, एक राष्ट्रीय बाजार का निर्माण हुआ और अर्थव्यवस्था के औपचारीकरण में काफी तेजी आई। यही नहीं, जीएसटी करदाता वर्ष 2017 में 66 लाख से बढ़कर वर्ष 2025 में 1.51 करोड़ हो गए

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद् ने तीन सितंबर को अब अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों को मंजूरी दे दी, जिसमें आम आदमी के जीवन में सुधार लाने और छोटे व्यापारियों और व्यापारियों सहित सभी के लिए व्यापार करने में सुगमता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने घोषणा की थी— "सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा। यह आपके लिए दिवाली का तोहफा होगा।" उन्होंने कहा कि सुधारों से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के परिवारों को प्रत्यक्ष लाभ होगा, जबकि भारत की दीर्घकालिक वृद्धि को सुदृढ़ किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि 1 जुलाई, 2017 को लागू किया गया वस्तु और सेवा कर (जीएसटी), स्वतंत्रता के बाद से भारत का सबसे महत्वपूर्ण

अप्रत्यक्ष कर सुधार है। कई केंद्रीय और राज्य करों को एक एकल, एकीकृत प्रणाली में एक साथ लाकर 'जीएसटी' ने एक सामान्य राष्ट्रीय बाजार का निर्माण किया, करों की आवर्ती को कम किया, सरलीकृत अनुपालन और पारदर्शिता में सुधार किया। आठ वर्षों में जीएसटी दर युक्तिकरण और डिजिटलीकरण के माध्यम से तेजी से विकसित हुआ है, जो भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे की रीढ़ बन गया है।

प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप जीएसटी परिषद् ने एक व्यापक सुधार पैकेज की अनुशंसा की, जिसमें सरलीकृत दो-स्लैब संरचना (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) के साथ दर युक्तिकरण, आम आदमी, श्रम-केंद्रित उद्योगों, किसानों और कृषि, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था के प्रमुख चालकों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ सेक्टरों में दरों में कटौती शामिल है। ये अनुशंसाएं जीएसटी परिषद् के सभी सदस्यों के बीच जीएसटी को सरल, निष्पक्ष और अधिक विकास-उन्मुख बनाने के लिए आम सहमति पर आधारित हैं। संशोधित दरें और छूट 22 सितंबर, 2025 से लागू होंगी, जिससे आम आदमी, परिवारों, किसानों और व्यवसायों के लिए समय पर राहत सुनिश्चित होगी।

सरलीकृत संरचना, अलग-अलग सेक्टरों को राहत

नवीनतम सुधार जीएसटी संरचना का एक बड़ा सरलीकरण है। पहले की 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत दरों को हटाकर 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दो-स्लैब प्रणाली में बदलाव से कराधान अधिक पारदर्शी और पालन में सुगम हो जाएगा। इसके साथ-साथ पान मसाला, तंबाकू जैसे मादक पदार्थों और एरेटेड ड्रिंक्स, महंगी कारों, नौकाओं और निजी विमानों जैसे लक्जरी उत्पादों पर 40 प्रतिशत की दर निष्पक्षता और राजस्व संतुलन सुनिश्चित करता है। इसके साथ ही, पंजीकरण और रिटर्न फाइलिंग को सरल बनाया गया है, रिफंड में तेजी लाई गई है और अनुपालन लागत कम की गई है, जिससे व्यवसायों, विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप पर बोझ कम हो गया है।

जीएसटी सुधार: क्षेत्रवार विवरण

खाद्य और घरेलू सेक्टर

इन सुधारों से रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं और पैकेज्ड खाद्य पदार्थों पर करों को कम किया गया है, जिससे परिवारों में प्रत्यक्ष बचत होगी। एसी, डिशवॉशर और टीवी (एलसीडी, एलईडी) पर जीएसटी दर में कटौती दोहरी जीत है। यह भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण इको-सिस्टम को सुदृढ़ करते हुए उपभोक्ताओं के लिए वहनीयता बढ़ाता है।

- अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) दूध, प्री-पैकेज्ड और लेबल वाले छेना या पनीर जैसे उत्पादों पर दरें शून्य होंगी।
- साबुन, शैंपू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, टेबलवेयर, साइकिल जैसे घरेलू सामान पर जीएसटी दर अब 5 प्रतिशत कर दी गई है।
- खाद्य पदार्थ जैसे पैकबंद नमकीन, भुजिया, सॉस, पास्ता, चॉकलेट, कॉफी, संरक्षित मांस आदि को 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया गया।
- कन्ज्यूमर ड्यूरेबलः टीवी (एलसीडी/एलईडी) (>32'), एसी, डिशवॉशर पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई।

गृह निर्माण एवं सामग्री

सीमेंट और निर्माण सामग्री पर जीएसटी में कटौती से हाउसिंग सेक्टर को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इससे घरों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की लागत कम होगी, जिससे घर खरीदना अधिक किफायती हो जाएगा। इस कदम से रियल एस्टेट में मांग बढ़ने और निर्माण में नए रोजगार सृजित होने की भी उम्मीद है।

- सीमेंट पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई।

जीएसटी दरों में कटौती व सुधारों से आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को फायदा होगा: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने तीन सितंबर को केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद् की तरफ से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सामूहिक रूप से सहमति व्यक्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा। श्री मोदी ने कहा, "व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित होगी।"

प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया, "अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण के दौरान मैंने जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के हमारे इरादे के बारे में बात की थी। केंद्र सरकार ने व्यापक रूप से जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने और इससे जुड़ी प्रक्रिया में सुधार के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूती देना है।"

उन्होंने कहा कि यह बताते हुए खुशी हो रही है कि केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद् ने सामूहिक रूप से केंद्र सरकार द्वारा जीएसटी दरों में कटौती और सुधारों पर प्रस्तुत प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की है, जिससे आम आदमी, किसानों, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाओं और युवाओं को लाभ होगा।

श्री मोदी ने कहा कि व्यापक सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए कारोबारी सुगमता सुनिश्चित करेंगे। ■

- संगमरमर/ट्रैवर्टीनब्लॉक, ग्रेनाइट ब्लॉक, रेत-चूना ईंटें पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- बांस फर्श/जॉइनरी, पैकिंग मामलों और पैलेट (लकड़ी) पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।

ऑटोमोबाइल सेक्टर

- छोटी कार, दोपहिया 350सीसी पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई।
- बसें, ट्रक, तिपहिया, सभी ऑटो पार्ट्स पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गई।

कृषि सेक्टर

सस्ती मशीनरी और जैव-कीटनाशकों पर निम्न दरों से छोटे किसानों को लागत कम करने और टिकाऊ कृषि कार्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

- ट्रैक्टर पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- टायर और पुर्जे पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- हार्वेस्टर, थ्रेशर, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई, पोल्ट्री और मधुमक्खी पालन मशीन पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- जैव-कीटनाशक और प्राकृतिक मेन्थॉल पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।

सेवा क्षेत्र

- होटल 7,500 रुपये प्रतिदिन तक ठहराव पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- जिम, सैलून, नाई पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।

खिलौने, खेल और हस्तशिल्प

मानव निर्मित फाइबर के लिए शुल्क ढांचा तय करने से वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता, विशेषकर निर्यात में सुधार होगा। इस क्षेत्र में इन्वर्टेड शुल्क संरचना को मानव निर्मित फाइबर पर जीएसटी दर को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और मानव निर्मित यार्न पर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने के साथ ठीक किया गया है।

- हस्तशिल्प की मूर्तियों और प्रतिमाओं पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- पेंटिंग, मूर्तियों पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- लकड़ी/धातु/कपड़ा गुड़िया और खिलौनेः 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत।

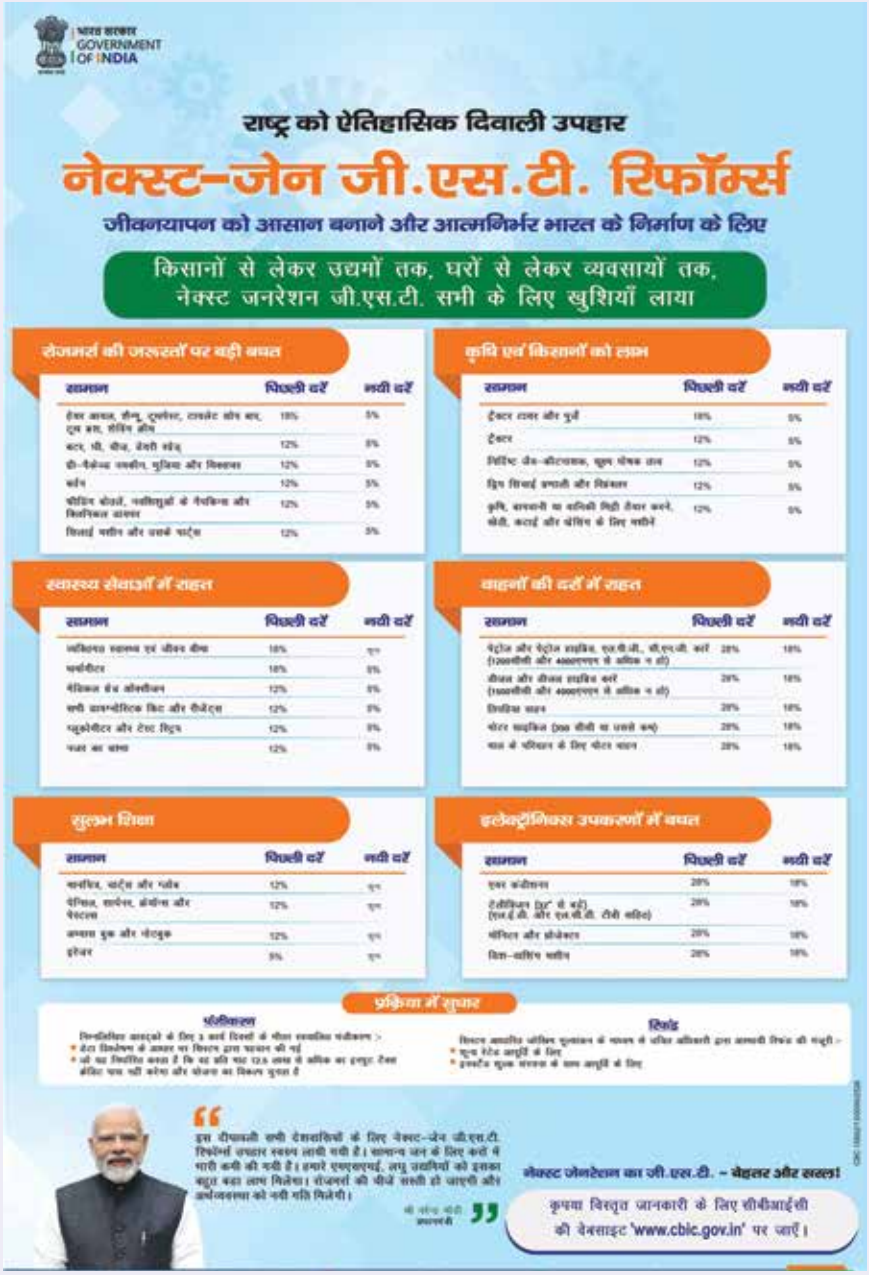

हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 04 सितंबर, 2025 को ऐतिहासिक जीएसटी सुधारों का स्वागत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को लाल किले की प्राचीर से अपने 11वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने के सरकार के इरादे के बारे में बात की थी। उनके यशस्वी नेतृत्व में केवल 20 दिन में ही जीएसटी काउंसिल ने ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया है या फिर काफी कम कर दिया है। नई जीएसटी व्यवस्था में 28 प्रतिशत और 12 प्रतिशत का स्लैब ही ख़त्म कर दिया गया है। यानी अब सिर्फ दो टैक्स स्लैब होंगे- 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत।

श्री नड्डा ने कहा कि मैं इस ऐतिहासिक नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म्स के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस सुधारों को जमीन पर उतारने के लिए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण, जीएसटी काउंसिल और भारत के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को भी साधुवाद देता हूं।

उन्होंने कहा कि ये रिफॉर्म्स हमारे नागरिकों के जीवन को तो बेहतर बनाएंगे ही, साथ ही छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार सुगमता भी सुनिश्चित करेंगे। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं, बल्कि देश के हर नागरिक की जीवन गुणवत्ता सुधारना है। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूती प्रदान करेगा और नई उम्मीदें जगाएगा।

श्री नड्डा ने कहा कि दूध, आंटा सहित रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी को जीरो कर दिया गया है। साथ ही, आम आदमी के उपयोग की कई वस्तुओं पर टैक्स को 12%, 18% या 28% से घटाकर सिर्फ 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इससे रोजमर्रा की इन आवश्यकताओं की कीमतों में भारी गिरावट आएगी और आम जनता की जेब पर टैक्स का बोझ भी कम होगा। जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा पर भी जीएसटी को जीरो कर दिया गया है। यह कदम आम जनता के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। महंगे घरेलू उपकरणों और वाहनों पर भी टैक्स दरों में भारी कटौती की गई है। खेती-बाड़ी में उपयोग होने वाली ट्रैक्टर, मशीनरी, कटाई-थ्रेसिंग उपकरण आदि पर टैक्स काफी घटा दिया गया है। इससे कृषि आधारित अर्थव्यस्था को एक नई मजबूती मिलेगी। घर के निर्माण में काम आने वाली सामग्रियों पर भी टैक्स दरों को कम किया गया है। इससे आम नागरिकों पर वित्तीय बोझ तो कम होगा ही, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार जीएसटी लागू ही नहीं कर पाई थी, क्योंकि राज्यों को तब की कांग्रेस सरकार पर भरोसा नहीं था। उलटे कांग्रेस सरकार वैट के माध्यम से गरीब जनता और व्यापारियों पर डाके डालती थी। साथ ही, बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की भी गुंजाइश बनी रहती थी, जबकि जीएसटी ने 'एक राष्ट्र, एक कर' की अवधारणा को चरितार्थ किया है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी में सारे निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं। हर महीने का रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन बताता है कि देश आर्थिक समृद्धि पर तेज गति से अग्रसर है। कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह है कि जीएसटी काउंसिल में तो इनके नेता समर्थन करते हैं, लेकिन बाहर राहुल गांधी उन्हीं फैसलों का विरोध करते हैं।

श्री नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का दृष्टिकोण अलग है— वे नागरिकों को वास्तविक राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं। जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दुर्गापूजा, दशहरा और दिवाली से पहले ही प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देशवासियों को 'बम्पर गिफ्ट' दिया है। ■

शिक्षा क्षेत्र

अभ्यास पुस्तिकाओं, इरेज़र, पेंसिल, क्रेयॉन और शार्पनर के साथ शिक्षा अधिक सस्ती हो गई है, जो 0 प्रतिशत जीएसटी के दायरे में आ गई हैं। इससे सीधे परिवारों और छात्रों को सहायता प्राप्त होगी, जिससे सीखने की सामग्री की कम लागत सुनिश्चित होगी।

- ज्यामिति बक्से, स्कूल डिब्बों, ट्रे पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।

चिकित्सा क्षेत्र

दवाओं और चिकित्सा उपकरणों पर कम दरों से स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच में सुधार होगा और फार्मा तथा चिकित्सा उपकरण क्षेत्रों में घरेलू विनिर्माण को सहायता प्राप्त होगी।

- 33 जीवन रक्षक दवाएं, डायग्नोस्टिक किट पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 0 प्रतिशत की गई।
- आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी सहित अन्य दवाएं पर जीएसटी दर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- चश्मा और सुधारात्मक चश्मे पर जीएसटी दर 28 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- चिकित्सा ऑक्सीजन, थर्मामीटर, सर्जिकल उपकरण पर जीएसटी दर 12 या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- चिकित्सा, दंत चिकित्सा और पशु चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की गई।

यह सुधार जीवन को आसान बनाएंगे: राजनाथ सिंह

केंद्रीय मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सभी क्षेत्रों को राहत पहुंचाने के लिए अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों की घोषणा की है।

कई महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कर दरों में कमी के साथ, यह सुधार जीवन को आसान बनाएंगे, व्यापार करने में आसानी को और मजबूती प्रदान करेंगे, छोटे व्यवसायों को सशक्त बनायेंगे और आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देंगे।

मैं इस साहसिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री श्री मोदी और वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को धन्यवाद देता हूं।" ■

भारत के लिए वास्तव में परिवर्तनकारी निर्णय: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी अपने वादे पर अडिग रहते हैं।

जीएसटी दर में कटौती और प्रक्रिया सुधारों का यह ऐतिहासिक निर्णय गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देगा, साथ ही किसानों, एमएसएमई, महिलाओं एवं युवाओं को भी सहारा देगा।

व्यवस्था को सरल बनाकर और आम नागरिकों पर बोझ कम करके, ये सुधार न केवल जीवनयापन में आसानी सुनिश्चित करेंगे, बल्कि व्यापार करने में आसानी को भी बढ़ावा देंगे, खासकर छोटे व्यापारियों और उद्यमियों के लिए।

भारत के लिए एक वास्तव में परिवर्तनकारी निर्णय!" ■

स्वास्थ्य और जीवन बीमा

- जीवन और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी छूट वित्तीय सुरक्षा का विस्तार करेगी और 2047 तक सभी के लिए मिशन बीमा के विजन का समर्थन करेगी।
- व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, फ्लोटर प्लान और वरिष्ठ नागरिक पॉलिसियों के प्रीमियम पर जीएसटी छूट।

जीएसटी से करों में उल्लेखनीय कमी आई है: निर्मला सीतारमण

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, "जीएसटी ने पूर्व-जीएसटी काल में लगाए गए औसत करों में उल्लेखनीय कमी की है, जिससे सभी परिवारों एवं क्षेत्रों को समान रूप से राहत मिली है।" ■

अगली पीढ़ी के लिए जीएसटी: सभी के लिए लाभ

- अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार न केवल कर दरों को कम करने के लिए बल्कि विकास का एक अच्छा चक्र बनाने के लिए भी डिज़ाइन किए गए हैं।
- **कम कीमतें, उच्च मांग:** सस्ती वस्तुएं और सेवाएं घरेलू बचत को बढ़ाती हैं और उपभोग को प्रोत्साहित करती हैं।
- **एमएसएमई के लिये सहायता:** सीमेंट, ऑटो पार्ट्स और हस्तशिल्प जैसे इनपुट पर कम दरें लागत कम करती हैं और छोटे व्यवसायों को अधिक प्रतिस्पर्द्धी बनाती हैं।
- **जीवन की सुगमता:** दो दरों की संरचना का अर्थ है कम विवाद, त्वरित निर्णय और सरल अनुपालन।
- **व्यापक कर नेट:** सरल दरें अनुपालन को प्रोत्साहित करती हैं, कर आधार का विस्तार करती हैं और राजस्व में सुधार करती हैं।
- **विनिर्माण के लिये सहायता:** इन्वर्टेड शुल्क संरचनाओं को ठीक करने से घरेलू मूल्य संवर्धन और निर्यात को बढ़ावा मिलता है।
- **राजस्व वृद्धि:** जैसाकि पिछले सुधारों में देखा गया है, बेहतर अनुपालन के साथ कम दरें संग्रह में वृद्धि करती हैं।
- **आर्थिक गति:** कम लागत → उच्च मांग → बड़ा कर आधार → मजबूत राजस्व → सतत विकास।
- **सामाजिक सुरक्षा:** बीमा और आवश्यक दवाओं पर जीएसटी की छूट घरेलू सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को सुदृढ़ करती है।

अब तक का निष्पादन

- जीएसटी को औपचारिक रूप से 1 जुलाई, 2017 की आधी रात को लागू किया गया था, जिसमें 17 अलग-अलग करों और 13 उपकरों को एक समेकित कर में समाहित कर दिया गया।
- **कर आधार का विस्तार:** जीएसटी करदाता आधार वर्ष 2017 में 66 लाख से बढ़कर वर्ष 2025 में 1.51 करोड़ हो गया है, जो अर्थव्यवस्था के अधिक औपचारीकरण को दर्शाता है।
- **रिकॉर्ड राजस्व वृद्धि:** वित्त वर्ष 2024-25 में 22.08 लाख करोड़ रुपए का सकल जीएसटी संग्रह दर्ज किया गया, जो 18 प्रतिशत की सीएजीआर के साथ केवल चार वर्षों में दोगुना हो गया। ■

‘राष्ट्र जीएसटी व्यवस्था में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देता है’

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने 07 सितंबर, 2025 को भाजपा संसदीय दल की कार्यशाला में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जो सर्वसम्मति से पारित हुआ

‘कर व्यवस्था’ किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु होती है। हालांकि, किसी भी सरकार की असली परीक्षा एक ऐसी कर व्यवस्था विकसित करने में होती है जो उत्पादन को बढ़ावा दे, खपत को प्रोत्साहित करे और साथ ही देश के कोष में उल्लेखनीय वृद्धि करे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में हाल ही में शुरू किए गए जीएसटी के सुधारों में सभी प्रमुख उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता है। इसके लिए हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

भाजपा सांसदों की यह सभा प्रधानमंत्री जी को इस साहसिक एवं आम जनता के लिए उठाए गए कदम के लिए हार्दिक बधाई देती है और जनता की ओर से आभार व्यक्त करती है।

आठ साल पहले माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व में भारत ने ‘एक राष्ट्र, एक कर’ के दृष्टिकोण को साकार करते हुए वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अपनाया। इसके पश्चात्, वैट एवं अनेक करों की जटिल व्यवस्था जिसने हमारी अर्थव्यवस्था को धीमी एवं खंडित कर रखी थी, राज्यों के बीच टोल बूथों को अनंत कतारों में जकड़ा हुआ था, अब वह पूरी तरह एक सुव्यवस्थित कर ढांचे और एकीकृत बाजार में बदल चुकी है। इससे हमारी अर्थव्यवस्था में न्यायसंगत, सरल एवं सुदृढ़ बना दिया है। 2014 से पहले सरकारें जीएसटी लागू करने में असफल रहीं, लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने न केवल जीएसटी लागू किया, बल्कि पूरे देश की सर्वसम्मति से इसे स्थापित भी किया। केवल 8 वर्षों में जीएसटी करदाताओं का आधार 2017 के 66 लाख से दोगुने से भी अधिक बढ़कर 1.5 करोड़ से अधिक हो गया है और वार्षिक कर संग्रह 18 प्रतिशत से अधिक की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में 22 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। जीएसटी संग्रह अब लगभग 2 लाख करोड़ रुपये प्रति माह तक पहुंच गया है, जो इस ऐतिहासिक सुधार के लागू होने के समय की तुलना में बहुत अधिक है। ‘डेलॉइट’ के एक सर्वेक्षण से पुष्टि होती है कि एमएसएमई सहित 85 प्रतिशत व्यवसाय जीएसटी से संतुष्ट हैं।

प्रधानमंत्री जी के दृढ़ विश्वास से प्रेरित इस सुधार के अगले चरण ने अब कर व्यवस्था को और सरल बना दिया है। इस पूरे प्रयास में आम लोगों को केंद्र में रखा गया है। खाद्य एवं दवाइयों जैसी आवश्यक वस्तुओं तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की दरें कम की गई हैं, इनवर्टेड टैक्स जैसी विकृतियों को दूर किया जा रहा है और छोटे व्यवसायों, निर्यातकों एवं स्टार्टअप्स के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाया जा रहा है। ये सुधार नागरिकों के जीवन को आसान बनाने, व्यापारियों को सशक्त बनाने और भारत को आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ाने के हमारी सरकार के दृढ़ संकल्पों को दर्शाते हैं। मासिक संग्रह में लगातार वृद्धि (2 लाख करोड़ रुपये), अधिक अनुपालन का एक निश्चित संकेत है। यह अर्थव्यवस्था में तेजी का भी संकेत है।

इसलिए, यह प्रस्ताव बड़े और छोटे सभी उत्पादकों/व्यापारियों से आह्वान करता है कि वे यह सुनिश्चित करने प्रयास करें कि छूट और रियायतों का लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचें। हर बचत और हर राहत को ग्राहकों तक पहुंचाकर हम प्रधानमंत्री जी के दृष्टिकोण को आगे ले जाने में सहयोग करेंगे और साथ ही दुकानदार एवं ग्राहक, व्यापारी एवं नागरिकों के बीच विश्वास भी बढ़ेगा। कम कीमतें मांग को बढ़ावा देंगी, मांग बढ़ने से व्यवसायों में तेजी आएगी तथा यह समृद्धि राष्ट्र की शक्ति को और मजबूती प्रदान करेगी।

आइए, हम यह सुनिश्चित करें कि श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी सुधारों को सुशासन की जीत और भारत की जनता से किए गए वादे के रूप में याद किया जाए। ये दूरगामी बदलाव हमारी एकता, निष्पक्षता और साझा विकास के प्रतीक हैं। अब प्रत्येक व्यापारी का कर्तव्य है कि वह राहत का एक-एक रुपया उपभोक्ता तक पहुंचाए, जिससे इन सुधारों को जीवन-जीने में आसानी, बढ़ती मांग और अधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था में बदला जा सके। यह मोदी सरकार का आह्वान है। यह न्यायसंगत विकास और भारत के प्रत्येक परिवार को इसका लाभ दिलाने का आह्वान है। यह एक ‘आत्मनिर्भर भारत’ का आह्वान है। ■

एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की भव्य जीत

सीपी राधाकृष्णन ने भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली

श्री चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने 12 सितंबर, 2025 को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति, केन्द्रीय मंत्री, विभिन्न प्रदेशों के मुख्यमंत्री, विपक्षी नेता एवं कई गणमान्य व्यक्ति इस समारोह में शामिल हुए।

शपथ ग्रहण कार्यक्रम के पश्चात् श्री राधाकृष्णन ने राजघाट पर महात्मा गांधी, सदैव अटल पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी एवं किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री श्री चरण सिंह की स्मृति में पुष्पांजलि अर्पित की।

संसद भवन में राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू, राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल और श्री एल. मुरुगन तथा राज्यसभा महासचिव ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मंत्रियों और राज्यसभा के अधिकारियों की उपस्थिति में संसद परिसर में एक पौधा भी लगाया।

इसके बाद श्री राधाकृष्णन ने संसद में विभिन्न राजनैतिक दलों के सदन के नेताओं के साथ बैठक की।

उल्लेखनीय है कि 9 सितंबर, 2025 को घोषित चुनाव परिणामों में एनडीए उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन ने इंडी गठबंधन के उम्मीदवार एवं सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश श्री बी. सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों के भारी अंतर से हराया था। उपराष्ट्रपति चुनाव की मतगणना के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए राज्यसभा के महासचिव और निर्वाचन अधिकारी श्री पीसी मोदी ने बताया कि कुल 781 मतदाताओं में से 767 सांसदों ने चुनाव में मतदान किया। उन्होंने बताया कि 767 मतों में से 752 वैध पाए गए और 15 अवैध घोषित किए गए। उन्होंने कहा, "मैं सी.पी. राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित घोषित करता हूं और चुनाव आयोग को परिणामों की सूचना प्रदान

प्रधानमंत्री ने सीपी राधाकृष्णन को चुनाव जीतने पर दी बधाई

चुनाव परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सीपी राधाकृष्णन से भेंट की और उन्हें उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने श्री सीपी राधाकृष्णन को 2025 का उपराष्ट्रपति चुनाव जीतने पर बधाई दी। 'एक्स' पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, "थिरु सी.पी. राधाकृष्णन जी को 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने पर बधाई। वे एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज सेवा और गरीबों व वंचितों के सशक्तीकरण के लिए समर्पित कर दिया है। मुझे विश्वास है कि वे एक उत्कृष्ट उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे जो हमारे संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करेंगे और संसदीय संवाद को बेहतर बनाएंगे।" ■

सीपी राधाकृष्णन का जीवन परिचय

पूरा नाम	श्री चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन
जन्मतिथि	श्री राधाकृष्णन का जन्म 20 अक्टूबर, 1957 को तमिलनाडु के तिरुप्पुर में श्री सीके पोन्नुसामी एवं श्रीमती के. जानकी के घर हुआ था।
शिक्षा	उन्होंने तमिलनाडु के थूथुकुडी के वी.ओ. चिदंबरम कॉलेज से बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) की डिग्री ली।
जुड़ाव	16 वर्ष की आयु से ही श्री राधाकृष्णन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं भारतीय जनसंघ जैसे संगठनों से जुड़े रहे हैं।
प्रमुख राजनीतिक दायित्व	◆ भाजपा तमिलनाडु प्रदेश मंत्री (1996) रहे। ◆ श्री राधाकृष्णन वर्ष 1998 एवं 1999 में कोयंबटूर लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए लोकसभा के लिए चुने गए। ◆ वह 2004 से 2006 तक भारतीय जनता पार्टी तमिलनाडु प्रदेश अध्यक्ष रहे। ◆ वह भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी रहे। ◆ भाजपा केरल प्रदेश प्रभारी (2020-22) रहे।
प्रशासनिक दायित्व	वह 2016 से 2020 तक भारतीय कॉयर बोर्ड के अध्यक्ष रहे।
राज्यपाल	◆ वह झारखंड के राज्यपाल (2023-24) रहे। ◆ 19 मार्च, 2024 को उन्हें तेलंगाना के राज्यपाल एवं पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया। ◆ वह महाराष्ट्र के राज्यपाल (2024-वर्तमान) बने।
एनडीए नामांकन	भारत के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार (2025) घोषित हुए ■

आपके सफल और प्रभावी कार्यकाल के लिए प्रार्थना करता हूं: जगत प्रकाश नड्डा

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी से मुलाकात की और उन्हें शुभकामनाएं दीं। श्री नड्डा ने कहा, "राष्ट्र के प्रति आपका समर्पण, दीर्घकालीन प्रशासनिक और राजनीतिक अनुभव एवं राष्ट्रहित में निरंतर कार्य करने की भावना से उच्च सदन में लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक परंपराएं और अधिक सशक्त व समृद्ध होंगी। मैं ईश्वर से आपके सफल एवं प्रभावी कार्यकाल की कामना करता हूं।"

थिरु सीपी राधाकृष्णन जी को शानदार जीत पर बधाई: राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति थिरु सीपी राधाकृष्णन जी से भेंट की और उनकी शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी।

उन्होंने कहा, "श्री सीपी राधाकृष्णन जी को भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई। अपने विशिष्ट सार्वजनिक जीवन में उन्होंने विनम्रता, सत्यनिष्ठा और सेवा के प्रति गहरी प्रतिबद्धता का परिचय दिया है। उनका विशाल अनुभव, संवैधानिक और विधायी मामलों का गहन ज्ञान और जनता के साथ अटूट जुड़ाव उनकी नई भूमिका को और समृद्ध करेगा।"

मुझे विश्वास है कि आपके नेतृत्व में राज्यसभा नई ऊंचाइयों को छुएगी और हमारी संसदीय परंपराएं और भी मजबूत होंगी। आपके सफल एवं प्रभावशाली कार्यकाल के लिए मेरी शुभकामनाएं।" ■

आपका कार्यकाल निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र में नए मील के पत्थर स्थापित करेगा: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने श्री सीपी राधाकृष्णन जी से उनकी शानदार जीत के बाद मुलाकात की। उन्होंने श्री राधाकृष्णन को उनकी जीत पर बधाई दी और उनके आगामी कार्यकाल के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दीं। यह कार्यकाल निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र में नए मील के पत्थर स्थापित करेगा और राजनीतिक विमर्श के मानकों को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा।

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा, "मुझे पूरा विश्वास है कि जमीनी स्तर से उठे एक नेता के रूप में आपकी दूरदर्शिता और प्रशासन के बारे में गहन जानकारी, हाशिए पर पड़े लोगों की सेवा के लिए हमारे संसदीय लोकतंत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रणालियां लाने में हमारी मदद करेगी। उच्च सदन की पवित्रता के संरक्षक के रूप में आपकी यात्रा के लिए मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।" ■

की जाएगी।"

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ 427 सांसदों का समर्थन था, साथ ही वाईएसआरसीपी के 11 सांसद भी एनडीए के पक्ष में थे। कुछ छोटे दलों के सांसदों ने भी एनडीए के उम्मीदवार का समर्थन किया। इससे श्री राधाकृष्णन की जीत लगभग तय हो गई थी, लेकिन अंतिम संख्या भाजपा समेत सभी की उम्मीदों से कहीं अधिक रही। श्री राधाकृष्णन को कुल वैध मतों के 60 प्रतिशत मिले, जबकि न्यायमूर्ति रेड्डी (सेवानिवृत्त) को 40 प्रतिशत मत मिले।

एनडीए उम्मीदवार की जीत का भारी अंतर विपक्षी इंडी गठबंधन के लिए झटका था, जिसने दावा किया था कि उसके साथ 315 सांसद का समर्थन है और उन्होंने रेड्डी को वोट दिया है।

उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 9 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सबसे पहले वोट डाला। इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, श्री राजनाथ सिंह, श्री अमित शाह, श्री जगत प्रकाश नड्डा, श्री नितिन गडकरी, श्री अश्विनी वैष्णव और श्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्रियों एवं सांसदों ने भी मतदान किया।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने संवाददाताओं को बताया, "उपराष्ट्रपति का चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष तरीके से होता है, मतदान गोपनीयता के साथ होता है और कई विपक्षी सांसदों ने भी श्री सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में मतदान किया है, जिससे पता चलता है कि सांसदों ने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर मतदान किया है।"

तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री सीपी राधाकृष्णन झारखंड, तेलंगाना, पुडुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल भी रह चुके हैं। ■

संभाग कार्यकर्ता बैठक, जबलपुर (मध्य प्रदेश)

देश के लिए कांग्रेस अमावस्या है, तो भाजपा पूर्णमासी की तरह है : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 25 अगस्त, 2025 को मध्यप्रदेश के जबलपुर में जबलपुर, रीवा, सागर और शहडोल संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित किया। इससे पहले जबलपुर में उनका भव्य स्वागत हुआ। श्री नड्डा ने कार्यकर्ताओं से कहा कि जनता को बताएं कि भाजपा और कांग्रेस में फर्क है कि देश के लिए कांग्रेस अमावस्या है, तो भारतीय जनता पार्टी पूर्णमासी की तरह है। इस बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष व विधायक श्री हेमंत खण्डेलवाल एवं प्रदेश संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी ने भी संबोधित किए। बैठक के दौरान प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह, केन्द्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार, उप-मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल, प्रदेश शासन के मंत्री राकेश सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश शासन के मंत्री श्री प्रहलाद पटेल एवं पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री ओमप्रकाश धुर्वे, प्रदेश महामंत्री व सांसद सुश्री कविता पाटीदार एवं प्रदेश महामंत्री श्री रणवीर सिंह रावत मंचासीन रहे।

श्री नड्डा ने कहा कि वर्ष 2014 भारतीय राजनीति का टर्निंग पाइंट बना, जब प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कार्यभार संभाला। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रिस्पांसिबल, रिस्पांसिव और रिपोर्ट कॉर्ड वाली सरकारों का दौर शुरू किया। कांग्रेस नेता हमारी अर्थव्यवस्था को डेड इकॉनामी बता रहे हैं, जबकि भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

उन्होंने कहा कि देश में वैचारिक राजनीति पर आधारित दल समाप्त हो गए हैं, सिर्फ भाजपा ही ऐसा राजनीतिक दल है, जो वैचारिक है। हमारे लिए गर्व का विषय है कि हम ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम जो बात 1951-52 में कहते थे, वही बात आज भी कह रहे हैं। हमने सत्ता के लिए समझौते नहीं किए, रास्ता नहीं बदला। डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति के लिए 1953 में अपना बलिदान दिया। उसके बाद इसे लेकर अनेक यात्राएं निकाली गयीं, कई बार आंदोलन किए गए, कई राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल गए। अंततः 5 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में एनडी सरकार ने धारा 370 हटाकर जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बना दिया। 1989 में हमने पालमपुर में श्रीराम मंदिर के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करने का प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद कई आंदोलन हुए, लंबी लड़ाई चली। हमारे विरोधी हम पर कटाक्ष करते थे, आखिरकार 2024 में भव्य श्रीराम मंदिर बनकर तैयार हो गया। हमने जब ट्रिपल तलाक हटाने की बात कही, तो विरोधियों ने हमें प्रतिक्रियावादी और सांप्रदायिक कहा। लेकिन आप लोगों की ताकत और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की इच्छाशक्ति से ट्रिपल तलाक जैसी बुराई को भी हटा दिया गया। आश्चर्य की बात है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, सीरिया, ईरान जैसे मुस्लिम देशों में भी

जिसका प्रावधान नहीं था, उसे भारत में तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने जिंदा रखा। हमने वक्फ बोर्ड एक्ट भी पारित किया। जब भी हमें अवसर मिला, हमने वो करके दिखाया, जो हम कहते हैं।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा कार्यकर्ता आधारित दल है। भाजपा के 14 करोड़ कार्यकर्ता हैं और 2 करोड़ सक्रिय सदस्य हैं। हम 8.25 लाख बूथों पर काम करते हैं। हमारे 240 लोकसभा और 102 राज्यसभा सदस्य हैं। गुजरात में छठी बार और मध्यप्रदेश में चौथी बार हमारी सरकारें बनी हैं। गोवा और हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार बनी है। उत्तरप्रदेश में 35 साल बाद हमारी सरकार लगातार दोबारा बनी। उत्तराखंड, मणिपुर, असम और त्रिपुरा में भी हमारी सरकारें दोबारा बनी। लंबे समय बाद दिल्ली में हमारी सरकार बनी है।

श्री नड्डा ने कहा कि मध्यप्रदेश में 80 स्टेशन अमृत भारत स्टेशन बन रहे हैं। 10 साल पहले जबलपुर का एयरपोर्ट छपरे की तरह था और सिर्फ 1 विमान आता था। आज यहां 450 करोड़ रुपए का नया टर्मिनल बन गया है। ग्वालियर एयरपोर्ट बन गया है। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा 750 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा है। इंदौर में मेट्रो रेल शुरू हो गई है और उज्जैन का महाकाल महालोक प्रोजेक्ट 856 करोड़ रुपए का है। मध्यप्रदेश में 2014 के पहले प्रति व्यक्ति आय 12000 रुपए थी, जो आज 1.52 लाख रुपये है। लाडली बहना योजना में हर माह 1250 रुपये की राशि दी जा रही है। हजारों आदिवासी छात्रों को स्कॉलरशिप दी जा रही है। सिकल सेल एनीमिया को लेकर लगातार काम चल रहा है। प्रदेश के 80 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिलती है। क्या ये परिवर्तन नहीं है? श्री नड्डा ने कहा कि आज जैसा विपक्ष है, उतना गैर जिम्मेदाराना विपक्ष पहले कभी नहीं रहा। भाजपा और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का विरोध करते-करते विपक्ष देश का विरोध करने लगा है। हमें इनका ये व्यवहार जनता को बताना होगा। ■

'राइजिंग लीडर प्रोग्राम'

'स्पेस से लेकर स्टार्टअप्स तक भारतीय युवाओं का डंका सारी दुनिया में बज रहा है'

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 04 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित भाजपा केंद्रीय कार्यालय में 'राइजिंग लीडर प्रोग्राम' के तहत देश के कई विश्वविद्यालयों के छात्रों एवं युवा प्रतिभाओं से संवाद किया। विदित हो कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष हर वर्ष देश के युवा प्रतिभाओं से संवाद एवं अनौपचारिक वार्ता करते रहे हैं। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े, सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख श्री अनिल बलूनी, राष्ट्रीय मीडिया सह-प्रमुख एवं बिहार विधान परिषद् में भाजपा के मुख्य सचेतक डॉ. संजय मयूख सहित पार्टी के कई प्रवक्ता एवं वरिष्ठ नेता उपस्थित थे।

श्री नड्डा ने युवा प्रतिभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की युवा-केंद्रित पहल देश भर में युवाओं के लिए अवसर पैदा कर रही हैं और उन्हें सशक्त बना रही हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के 11 साल न केवल देश के आर्थिक, सामरिक और ढांचागत विकास में नए अध्याय लिख रहा है, बल्कि युवाशक्ति को भी निरंतर सशक्त करने में लगा है। बेहतर शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट से लेकर नौकरियों और व्यावसायिक सहायता तक, कई कदम उठाए गए हैं। स्पेस से लेकर स्टार्टअप्स तक भारतीय युवाओं का डंका सारी दुनिया में बज रहा है। हमारी सरकार में कई नए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज खुली हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत करोड़ों लोगों को प्रशिक्षित किया है और स्टार्टअप को बढ़ने में मदद की है। रोजगार मेला, खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रम युवाओं को नए अवसर देते हैं। नई शिक्षा नीति युवाओं के सपनों को उड़ान देते हुए नए भारत के विजन को साकार कर रही है।

कार्यक्रम में युवा प्रतिभाओं ने भी अपने विचार रखे और राष्ट्र पुनर्निर्माण के यज्ञ में योगदान देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई। बाद में सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए श्री नड्डा ने कहा कि उन्हें इस सत्र में देश के युवा प्रतिभाओं से संवाद कर बहुत आनंद आया और आने वाले दिनों में हमारे भावी नेताओं के साथ ऐसी और भी सार्थक बातचीत की आशा है। ■

कांग्रेस पार्टी चाहे कितना भी विरोध करे, भाजपा सरकार जमीन के हर इंच को घुसपैठियों से खाली कराने का काम करेगी : अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने 29 अगस्त, 2025 को असम के अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे और अंतिम दिन गुवाहाटी, असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के एनडीए पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन और असम राजभवन परिसर में ब्रह्मपुत्र विंग के उदघाटन कार्यक्रम को संबोधित किया। इन कार्यक्रमों में उन्होंने श्री नरेन्द्र मोदी सरकार में असम के विकास की गाथा पर विस्तार से चर्चा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव की निर्णायक लड़ाई का भी उल्लेख किया। साथ ही, उन्होंने बिहार में राहुल गांधी के मंच से कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी पूज्य दिवंगत माताजी के खिलाफ प्रयोग किए गए घोर अपशब्दों की भी निंदा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री दिलीप सैकिया, केन्द्रीय श्री सर्वानंद सोनवाल, असम सरकार में मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेट, असम गण परिषद् के अध्यक्ष श्री अतुल बोरा, भाजपा प्रदेश प्रभारी श्री हरीश द्विवेदी सहित अनेक नेतागण उपस्थित रहे।

पंचायत प्रतिनिधि सम्मेलन में बोलते हुए श्री शाह ने कहा कि असम के पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी के नेता विजय की आशा लगाए बैठे थे, मगर जब परिणाम आया, तो कांग्रेस पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया। असम पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी को ढूंढना हो तो दूरबीन लेकर भी ढूंढा नहीं जा सकता। यह प्रचंड विजय भाजपा कार्यकर्ताओं और असम की जनता ने प्राप्त की है। लगभग 20,000 नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, 15,000 पंचायत सदस्यों, 1500 ब्लॉक स्तर के सदस्यों, 750 म्युनिसिपल काउंसिलरों और 300 से अधिक जिला परिषद् सदस्यों को को बहुत-बहुत बधाई।

उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में श्री नरेन्द्र मोदी ने उत्तर-पूर्व में शांति का एक नया युग स्थापित किया है। श्री मोदी ने जिस विकास का नया दौर पूर्वोत्तर में शुरू किया, उसे मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा ने असम के हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। इसी का नतीजा है कि बार-बार भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होती है। जिला परिषद् चुनावों में 397 सीटों में से 301 सीटें भाजपा ने जीतीं। तहसील पंचायत में 2,188 सीटों में से 1445 सीटें एनडीए ने जीतीं और लगभग 15,000 पंचायत स्तर के प्रतिनिधि चुनकर आए। यह चुनाव विशेष महत्व रखता है, क्योंकि परिसीमन के बाद असम में यह पहला चुनाव था और 1980 के बाद पहली बार पंचायत चुनावों में 74% से अधिक मतदान हुआ और उसके परिणामस्वरूप भाजपा और एनडीए को ऐतिहासिक जीत मिली। लोकसभा में भी 14 में से 11 सीटें भाजपा के खाते में आईं, राज्यसभा की सभी 5 सीटों पर एनडीए विजयी हुआ और सभी उपचुनावों में में एनडीए को जीत मिली। कारबी आंग्लोंग स्वायत्त परिषद, उत्तरी कछार स्वायत्त परिषद् और राबा हसोंग स्वायत्त परिषद, तीनों जगहों पर भी एनडीए ने विजय हासिल की।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिस विकास का नया दौर पूर्वोत्तर में शुरू किया, उसे मुख्यमंत्री श्री हेमंत विश्व शर्मा ने असम के हर गांव और हर व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य किया। इसी का नतीजा है कि बार-बार भारतीय जनता पार्टी को विजय प्राप्त होती है

उन्होंने कहा कि असम की सबसे बड़ी समस्या घुसपैठियों की थी, जो नाबालिग बच्चियों से शादी कर सामाजिक संतुलन को बिगाड़ रहे थे। मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी ने इस पर सख्त अभियान चलाया और ऐसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया। गृह मंत्री ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने लाखों एकड़ भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराया है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई इस मुहिम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार संकल्पबद्ध है कि असम की एक-एक इंच भूमि को घुसपैठियों से मुक्त कराकर असम के युवाओं को उसका अधिकार दिलाया जाएगा। अब तक 3500 एकड़ चरागाह की भूमि, 87,000 एकड़ वन्यजीव अभयारण्य की भूमि, 26,000 एकड़ सरकारी भूमि और 4500 एकड़ अन्य भूमि घुसपैठियों से मुक्त कराई गई है। इसके अतिरिक्त 1548 एकड़ भूमि को भी मुक्त कराया गया है।

श्री शाह ने जनता से आह्वान किया कि हमें यह संकल्प लेकर आज जाना है कि आने वाले समय में असम में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनानी है, एनडीए की सरकार बनानी है, असम गण परिषद् और भाजपा की सरकार बनानी है। ■

राष्ट्र जीवन की समस्याएं

| पं. दीनदयाल उपाध्याय |

भारतीय जनसंघ के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं एकात्ममानव दर्शन के प्रणेता पं. दीनदयाल उपाध्याय कुशल संगठनकर्ता एवं मौलिक विचारक थे। निम्नलिखित लेख राष्ट्रधर्म (अंक-9, 6 अक्टूबर, 1949) से साभार प्रस्तुत है। इस लेख में दीनदयालजी ने अर्थवादी, राजनीतिवादी, मतवादी एवं संस्कृतिवादी विचारधाराओं का विश्लेषण करते हुए विचार व्यक्त किया है कि एक-संस्कृतिवादियों के साथ पूर्ण सहयोग करने की आवश्यकता है

भारत में एक ही संस्कृति रह सकती है; एक से अधिक संस्कृतियों का नारा देश के टुकड़े-टुकड़े करके हमारे जीवन का विनाश कर देगा। अतः आज लीग का द्विसंस्कृतिवाद, कांग्रेस का प्रच्छन्न द्विसंस्कृतिवाद तथा साम्यवादियों का बहुसंस्कृतिवाद नहीं चल सकता। आज तक एक-संस्कृतिवाद को संप्रदायवाद कहकर ठुकराया गया, किंतु अब कांग्रेस के विद्वान भी अपनी गलती समझकर इस एक-संस्कृतिवाद को अपना रहे हैं। इसी भावना और विचार से भारत की एकता तथा अखंडता बनी रह सकती है तथा तभी हम अपनी संपूर्ण समस्याओं को सुलझा सकते हैं।

मनुष्य की अनेक जन्मजात प्रवृत्तियों के समान वह देशभक्ति की भावना को भी स्वभाव से ही प्राप्त करता है। परिस्थितियां एवं वातावरण के दबाव से किसी व्यक्ति में यह प्रवृत्ति सुप्त प्रायः होकर विलीन हो जाती है। इस प्रकार विकसित देश प्रेम के व्यक्ति अपने कार्यकलापों की प्रेरणा अस्पष्ट एवं क्षीण भावना से न पाकर अपने स्वप्नों के अनुसार अपने देश का निर्माण करने की प्रबल ध्येयवादिता से पाते हैं। भारत में भी प्रत्येक देशभक्त के सम्मुख इस प्रकार का एक ध्येयपथ है तथा वह समझता है कि अपने पथ पर चलाकर ही वह देश को समुन्नत बना सकेगा। आज यह ध्येयपथ यदि एक ही होता तथा सब देशभक्तों के आदर्श भारत का स्वरूप भी एक ही होता तब तो किसी भी प्रकार के विवाद का संघर्ष का प्रश्न नहीं था। किंतु वस्तुस्थिति यह है कि आज भिन्न-भिन्न मार्गों से लोग देश को आगे ले जाना चाहते हैं तथा प्रत्येक का विश्वास है कि उसी का मार्ग सही मार्ग है। अतः हमको इन मार्गों का विश्लेषण करना होगा और उसी समय हम प्रत्येक की वास्तविकता को भी समझ सकेंगे।

चार प्रमुख मार्ग :

इन मार्गों को देखते हुए हमें चार प्रधान वर्ग दिखाई देते हैं— अर्थवादी, राजनीतिवादी, मतवादी तथा संस्कृतिवादी।

अर्थवादी: पहला वर्ग, अर्थवादी संपत्ति को ही सर्वस्व समझता है तथा उसके स्वामित्व एवं वितरण में ही सब प्रकार की दुरवस्था की जड़ मानकर उसमें सुधार करना ही अपना एकमेव कर्त्तव्य समझता है। उसका एकमेव लक्ष्य 'अर्थ' है। साम्यवादी एवं समाजवादी इस वर्ग के लोग हैं। इनके अनुसार भारत की राजनीति का निर्धारण अर्थनीति के आधार पर होना चाहिए तथा संस्कृति एवं मत को वे गौण समझकर अधिक महत्व देने को तैयार नहीं हैं।

राजनीतिवादी: राजनीतिवादी दूसरा वर्ग है। यह जीवन का संपूर्ण महत्व राजनीतिक प्रमुख प्राप्त करने में ही समझता है तथा राजनीतिक दृष्टि से ही संस्कृति, मजहब तथा अर्थनीति की व्याख्या करता है। अर्थवादी यदि एकदम उद्योगों का राष्ट्रीयकरण अथवा बिना मुआविजा दिए जमींदारी उन्मूलन चाहता है तो राजनीतिवादी अपने राजनीतिक कारणों से ऐसा करने में असमर्थ है। उसके लिए इस प्रकार संस्कृति एवं मजहब का भी मूल्य अपनी राजनीति के लिए ही है, अन्यथा नहीं। इस वर्ग के अधिकांश लोग कांग्रेस में हैं जो आज भारत की राजनीतिक बागडोर संभाले हुए हैं।

मतवादी: तीसरा वर्ग, मजहबपरस्त या मतवादी है। इसे धर्मनिष्ठ कहना ठीक नहीं होगा; क्योंकि धर्म मजहब या मत से बड़ा तथा विशाल है। यह वर्ग अपने-अपने मजहब के सिद्धांतों के अनुसार ही देश की राजनीति अथवा अर्थनीति को चलाना चाहता है। इस प्रकार का वर्ग मुल्ला-मौलवियों अथवा रूढ़िवादी कट्टरपंथियों के रूप में अब भी थोड़ा बहुत विद्यमान है, यद्यपि आजकल उसका बहुत प्रभाव नहीं रह गया है।

संस्कृतिवादी: चौथा वर्ग है। इसका विश्वास है कि भारत की आत्मा का स्वरूप प्रमुखतया संस्कृति ही है। अतः अपनी संस्कृति की रक्षा एवं विकास ही हमारा कर्त्तव्य होना चाहिए। यदि हमारा सांस्कृतिक ह्रास हो गया तथा हमने पश्चिम के अर्थ प्रधान अथवा भोग प्रधान जीवन को अपना लिया तो हम निश्चित ही समाप्त हो जाएंगे। यह वर्ग भारत में बहुत बड़ा है। इसके लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तथा कुछ अंशों में कांग्रेस में भी हैं। कांग्रेस के ऐसे लोग राजनीति को केवल संस्कृति का पोषकमात्र ही मानते हैं, संस्कृति को निर्णायक नहीं। हिंदीवादी सब लोग इसी वर्ग के हैं।

मार्गों की प्राचीनता :

उपर्युक्त चार वर्गों की विवेचना में यद्यपि हमने आधुनिक शब्दों का प्रयोग किया है। किंतु प्राचीन काल में भी ये चार प्रवृत्तियां उपस्थित थीं तथा इनमें से एक प्रवृत्ति को ही अपनाकर हमने अपने जीवन के आदर्श का मानदंड बनाया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही ये चार प्रवृत्तियां हैं। धर्म संस्कृति का, अर्थ नैतिक वैभव का, काम राजनीतिक आकांक्षाओं का तथा मोक्ष पारलौकिक उन्नति का द्योतक था। इनमें से हमने धर्म को ही अपने जीवन का अंग बनाया है क्योंकि उसके द्वारा ही हमने शेष सबको सधते हुए देखा है। इसीलिए जब महाभारत काल में धर्म की अवहेलना होनी प्रारंभ हुई, तब महर्षि व्यास ने कहा...

'ऊर्ध्वबाहुर्विरोम्येष न च कश्चिच्छणोति मे।
धर्मादर्थश्च कामश्च स धर्मः किं न सेव्यते॥'

अर्थ और काम की ही नहीं, मोक्ष की भी प्राप्ति धर्म से होती है; इसलिए धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है कि 'यतोऽभ्युदयनिःश्रेयस सिद्धिः स धर्मः।' जिससे ऐहिक संतान एक है और उसको इस एकता का अनुभव करते हुए रहना चाहिए। अनेक अंगों को इकट्ठा करके शरीर की सृष्टि नहीं होती, किंतु शरीर के अनेक अंग होते हैं और इसलिए प्रत्येक अवयव अपने स्वतंत्र अस्तित्व के लिए नहीं, अपितु शरीर के अस्तित्व के लिए प्रयत्न करता है। इसी प्रकार राष्ट्र के सभी अंगों को अपनी रूपरेखा राष्ट्रीय स्वरूप और हितों के अनुकूल बनानी चाहिए न कि राष्ट्र को ही इन अंगों के अनुसार काटा-छांटा जाए। संप्रदायों, प्रांतों, भाषाओं और वर्गों का तभी तक मूल्य है जब तक वे राष्ट्र हितों के अनुकूल हैं अन्यथा उनका बलिदान करके भी राष्ट्र की एकता की रक्षा करनी होगी।

प्रथम दृष्टिकोण में अनेक को सत्य मानकर एक की कल्पना का प्रयत्न है तो दूसरे में एक को सत्य मानकर अनेक उसके रूपमात्र हैं जैसे नदी के जल में आवर्त्त – विवर्त्त तरंग आदि अनेक रूप होते हैं किंतु उनका अस्तित्व नदी के जल से भिन्न और स्वतंत्र नहीं और न उनके समुच्चय का ही नाम नदी है। दुःख का विषय है कि आज भी देश की बागडोर, जिनके हाथ में हैं वे प्रथम दृष्टिकोण से ही समस्त समस्याओं को देखते हैं। जब तक राजनीति की इस मौलिक भूल का परिमार्जन नहीं होगा, तब तक राजनीतिक भारत का निर्माण सुदृढ़ नींव पर नहीं हो सकता।

धर्म प्रधान भारतीय जीवन :

भारतीय जीवन को धर्म प्रधान बनाने का प्रमुख कारण यह था कि इसी में जीवन के विकास की सबसे अधिक संभावना है। आर्थिक दृष्टिकोण वाले लोग यद्यपि आर्थिक समानता के पक्षपाती हैं, किंतु वे व्यक्ति की राजनीति एवं आत्मिक सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर देते हैं। राजनीतिवादी प्रत्येक व्यक्ति को मतदान का अधिकार देकर उसके राजनीतिक व्यक्तित्व की रक्षा तो अवश्य करते हैं, किंतु आर्थिक एवं आत्मिक दृष्टि से वे भी अधिक विचार नहीं करते। अर्थवादी यदि जीवन को भोग प्रधान बनाते हैं तो राजनीतिवादी उसको अधिकार प्रधान बना देते हैं। मतवादी बहुत कुछ अव्यावहारिक, गतिहीन एवं संकुचित हो जाते हैं। किसी-किसी व्यक्ति विशेष अथवा पुस्तक विशेष के विचारों के वे इतने गुलाम हो जाते हैं कि समय के साथ वे अपने आपको नहीं रख पाते तथा इस प्रकार पूर्णतः नष्ट हो जाते हैं। इन सबके विपरीत संस्कृति प्रधान जीवन की यह विशेषता है कि इसमें जीवन के केवल मौलिक तत्त्वों पर तो जोर दिया जाता है पर शेष बाह्य बातों के संबंध में प्रत्येक को स्वतंत्रता रहती है। इसके अनुसार व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षेत्र में विकास होता है। संस्कृति किसी काल विशेष अथवा व्यक्ति विशेष के बंधन से जकड़ी हुई नहीं है, अपितु यह तो स्वतंत्र एवं विकासशील जीवन की मौलिक प्रवृत्ति है। इस संस्कृति को ही हमने धर्म कहा है। अतः जब कहा जाता है कि भारतवर्ष धर्म प्रधान देश है तो इसका अर्थ मजहब, मत या रिलीजन नहीं, किंतु यह संस्कृति ही होता है।

भारत की विश्व को देन :

हमने देखा है कि भारत की आत्मा को समझना है तो उसे राजनीति अथवा अर्थ नीति के चश्मे से न देखकर सांस्कृतिक दृष्टिकोण से ही देखना होगा। भारतीयता की अभिव्यक्ति राजनीति के द्वारा न होकर उसकी संस्कृति के द्वारा ही होगी। विश्व को भी यदि हम कुछ सिखा सकते हैं तो उसे अपनी सांस्कृतिक सहिष्णुता एवं कर्तव्य प्रधान जीवन की भावना की ही शिक्षा दे सकते हैं, राजनीति अथवा अर्थ नीति की नहीं। उसमें तो शायद हमको उनसे ही उलटे भीख मांगनी पड़े। अर्थ, काम और मोक्ष के विपरीत धर्म की प्रमुख भावना ने भोग के स्थान पर त्याग, अधिकार के स्थान पर कर्त्तव्य तथा संकुचित असहिष्णुता के स्थान पर विशाल सहिष्णुता प्रकट की है। इनके साथ ही हम विश्व में गौरव के साथ खड़े हो सकते हैं।

संघर्ष का आधार :

भारतीय जीवन का प्रमुख तत्त्व उसकी संस्कृति अथवा धर्म होने के कारण उसके इतिहास में भी जो संघर्ष हुए हैं, वे अपनी संस्कृति की सुरक्षा के लिए ही हुए हैं। तथा इसी के द्वारा हमने विश्व में ख्याति भी प्राप्त की है। हमने बड़े-बड़े साम्राज्यों के निर्माण को महत्व न देकर अपने सांस्कृतिक जीवन को पराभूत नहीं होने दिया। यदि हम अपने मध्ययुग का इतिहास देखें तो हमारा वास्तविक युद्ध अपनी संस्कृति के रक्षार्थ ही हुआ है। उसका राजनीतिक स्वरूप यदि कभी प्रकट भी हुआ तो उस संस्कृति की रक्षा के निमित्त ही। राणाप्रताप तथा राजपूतों का युद्ध केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए नहीं था, किंतु धार्मिक स्वतंत्रता के लिए ही था। छत्रपति शिवाजी ने अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना गो-ब्राह्मण प्रतिपालन के लिए ही की। सिख-गुरुओं ने अपने युद्ध धर्म की रक्षा के लिए ही किए। इन सबका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि राजनीति का कोई महत्त्व नहीं था तथा राजनीतिक गुलामी हमने सहर्ष स्वीकार कर ली थी। किंतु तात्पर्य यह है कि राजनीति को हमने जीवन का केवल सुख का कारण मात्र माना है, जबकि संस्कृति संपूर्ण जीवन ही है। ■

क्रमशः

मोहन भागवत जी
'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के प्रबल समर्थक

नरेन्द्र मोदी

आज 11 सितंबर है। यह दिन अलग-अलग स्मृतियों से जुड़ा है। एक स्मृति 1893 की है, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में विश्व बंधुत्व का संदेश दिया और दूसरी स्मृति है 9/11 का आतंकी हमला, जब विश्व बंधुत्व को सबसे बड़ी चोट पहुंचाई गई। आज के दिन की एक और विशेष बात है। आज एक ऐसे व्यक्तित्व का 75वां जन्मदिवस है, जिन्होंने वसुधैव कुटुंबकम् के मंत्र पर चलते हुए समाज को संगठित करने, समता-समरसता और बंधुत्व की भावना को सशक्त करने में अपना पूरा जीवन समर्पित किया है।

संघ परिवार में जिन्हें परम पूजनीय सरसंघचालक के रूप में श्रद्धाभाव से संबोधित किया जाता है, ऐसे आदरणीय मोहन भागवत जी का आज जन्मदिन है। यह एक सुखद संयोग है कि इसी साल संघ भी अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। मैं भागवत जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर उन्हें दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करें।

मेरा मोहन भागवत जी के परिवार से बहुत गहरा संबंध रहा है। मुझे उनके पिता, स्वर्गीय मधुकरराव भागवत जी के साथ निकटता से काम करने का सौभाग्य मिला था। मैंने अपनी पुस्तक ज्योतिपुंज में मधुकरराव जी के बारे में विस्तार से लिखा भी है। वकालत के साथ-साथ मधुकरराव जी जीवनभर राष्ट्र निर्माण के कार्य में समर्पित रहे। अपनी युवावस्था में उन्होंने लंबा समय गुजरात में बिताया और संघ कार्य की मजबूत नींव रखी।

मधुकरराव जी का राष्ट्र निर्माण के प्रति झुकाव इतना प्रबल था कि अपने पुत्र मोहनराव को भी इस महान कार्य के लिए निरंतर गढ़ते रहे। एक पारसमणि मधुकरराव ने मोहनराव के रूप में एक और पारसमणि तैयार कर दी।

भागवत जी का पूरा जीवन सतत प्रेरणा देने वाला रहा है। वे 1970 के दशक के मध्य में प्रचारक बने। सामान्य जीवन में प्रचारक शब्द सुनकर ये भ्रम हो जाता है कि कोई प्रचार करने वाला व्यक्ति होगा, लेकिन जो संघ को जानते हैं उनको पता है कि प्रचारक परंपरा संघ कार्य की विशेषता है। गत 100 वर्षों में देशभक्ति की प्रेरणा से भरे हजारों युवक-युवतियों ने अपना घर-परिवार त्याग करके पूरा जीवन संघ परिवार के माध्यम से राष्ट्र को समर्पित किया है। भागवत जी भी उस महान परंपरा की मजबूत धुरी हैं।

> **भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी**

भागवत जी ने उस समय प्रचारक का दायित्व संभाला, जब तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश पर इमरजेंसी थोप दी थी। उस दौर में प्रचारक के रूप में भागवत जी ने आपातकाल-विरोधी आंदोलन को निरंतर मजबूती दी। उन्होंने कई वर्षों तक महाराष्ट्र के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों, विशेषकर विदर्भ में काम किया। 1990 के दशक में अखिल भारतीय शारीरिक प्रमुख के रूप में मोहन भागवत जी के कार्यों को आज भी कई स्वयंसेवक स्नेहपूर्वक याद करते हैं। इसी कालखंड में मोहन भागवत जी ने बिहार के गांवों में अपने जीवन के अमूल्य वर्ष बिताए और समाज को सशक्त करने के कार्य में समर्पित रहे।

वर्ष 2000 में वे सरकार्यवाह बने और यहां भी भागवत जी ने अपनी अनोखी कार्यशैली से हर कठिन परिस्थिति को सहजता और सटीकता से संभाला।

2009 में वे सरसंघचालक बने और आज भी अत्यंत ऊर्जा के साथ कार्य कर रहे हैं। भागवत जी ने राष्ट्र प्रथम की मूल विचारधारा को हमेशा सर्वोपरि रखा।

सरसंघचालक होना मात्र एक संगठनात्मक जिम्मेदारी नहीं है। यह एक पवित्र विश्वास है, जिसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दूरदर्शी व्यक्तित्वों ने आगे बढ़ाया है और इस राष्ट्र के नैतिक और सांस्कृतिक पथ को दिशा दी है। असाधारण व्यक्तियों ने इस भूमिका को व्यक्तिगत त्याग, उद्देश्य की स्पष्टता और मां भारती के प्रति अटूट समर्पण के साथ निभाया है। यह गर्व की बात है कि मोहन भागवत जी ने न केवल इस विशाल जिम्मेदारी के साथ पूर्ण न्याय किया है, बल्कि इसमें अपनी व्यक्तिगत शक्ति, बौद्धिक गहराई और सहृदय नेतृत्व भी जोड़ा है।

भागवत जी का युवाओं से सहज जुड़ाव है और इसलिए उन्होंने अधिक से अधिक युवाओं को संघ कार्य के लिए प्रेरित किया है। वे लोगों से प्रत्यक्ष संपर्क में रहते हैं और संवाद करते रहते हैं। श्रेष्ठ कार्यपद्धति को अपनाने की इच्छा और बदलते समय के प्रति खुला मन रखना, ये मोहनजी की बहुत बड़ी

विशेषता रही है। अगर हम व्यापक संदर्भ में देखते हैं तो संघ की 100 साल की यात्रा में भागवत जी का कार्यकाल संघ में सर्वाधिक परिवर्तन का कालखंड माना जाएगा। चाहे वो गणवेश परिवर्तन हो, संघ शिक्षा वर्गों में बदलाव हो, ऐसे अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन उनके निर्देशन में संपन्न हुए।

कोरोना काल में मोहन भागवत जी के प्रयास विशेष रूप से याद आते हैं। उस कठिन समय में उन्होंने स्वयंसेवकों को सुरक्षित रहते हुए समाजसेवा करने की दिशा दी और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाने पर बल दिया। उनके मार्गदर्शन में स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों तक हरसंभव सहायता पहुंचाई, जगह-जगह मेडिकल कैंप लगाए। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों और वैश्विक विचार को प्राथमिकता देते हुए व्यवस्थाओं को विकसित किया। हमें कई स्वयंसेवकों को खोना भी पड़ा, लेकिन भागवत जी की प्रेरणा ऐसी थी कि अन्य स्वयंसेवकों की दृढ़ इच्छाशक्ति कमजोर नहीं पड़ी।

इस वर्ष की शुरुआत में मैंने नागपुर में उनके साथ माधव नेत्र चिकित्सालय के उद्घाटन के दौरान मैंने कहा था कि संघ अक्षयवट की तरह है, जो राष्ट्रीय संस्कृति और चेतना को ऊर्जा देता है। इस अक्षयवट वृक्ष की जड़ें इसके मूल्यों की वजह से बहुत गहरी और मजबूत हैं। इन मूल्यों को आगे बढ़ाने में जिस समर्पण से मोहन भागवत जी जुटे हुए हैं, वो हर किसी को प्रेरणा देता है।

समाज कल्याण के लिए संघ की शक्ति के निरंतर उपयोग पर मोहन भागवत जी का विशेष बल रहा है। इसके लिए उन्होंने पंच परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें स्व बोध, सामाजिक समरसता, नागरिक शिष्टाचार, कुटुम्ब प्रबोधन और पर्यावरण के सूत्रों पर चलते हुए राष्ट्र निर्माण को प्राथमिकता दी गई है। देश और समाज के लिए सोचने वाले हर भारतवासी को पंच परिवर्तन के इन सूत्रों से अवश्य प्रेरणा मिलेगी।

संघ का हर कार्यकर्ता वैभव संपन्न भारत माता का सपना साकार होते देखना चाहता है। इस सपने को पूरा करने के लिए जिस स्पष्ट विज़न और ठोस एक्शन की जरूरत होती है, मोहन जी इन दोनों गुणों से परिपूर्ण हैं।

मोहन जी के स्वभाव की एक और बड़ी विशेषता ये है कि वो मृदुभाषी हैं। उनमें सुनने की भी अद्भुत क्षमता है। यह विशेषता न केवल उनके दृष्टिकोण को गहराई देती है, बल्कि उनके व्यक्तित्व और नेतृत्व में संवेदनशीलता और गरिमा भी लाती है।

मोहन जी हमेशा 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' के प्रबल पक्षधर रहे हैं। भारत की विविधता और भारत भूमि की शोभा बढ़ा रही अनेक संस्कृतियों और परंपराओं के उत्सव में भागवत जी पूरे उत्साह से शामिल होते हैं। वैसे बहुत कम लोगों को ये पता है कि मोहन भागवत जी अपनी व्यस्तता के बीच संगीत और गायन में भी रुचि रखते है। वे विभिन्न भारतीय वाद्ययंत्रों में भी निपुण हैं। पठन-पाठन में उनकी रुचि, उनके अनेक भाषणों और संवादों में साफ दिखाई देती है।

पिछले दिनों देश में जितने सफल जन-आंदोलन हुए चाहे स्वच्छ भारत मिशन हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोहन भागवत जी ने पूरे संघ परिवार को इन आंदोलनों में ऊर्जा भरने के लिए प्रेरित किया। मैं पर्यावरण से जुड़े प्रयासों और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाने के प्रति उनके समर्पण को जानता हूं। मोहन जी का बहुत जोर आत्मनिर्भर भारत पर भी है।

कुछ ही दिनों में विजयादशमी पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्ष का हो जाएगा। यह भी सुखद संयोग है कि विजयादशमी का पर्व, गांधी जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की जयंती और संघ का शताब्दी वर्ष एक ही दिन आ रहे हैं।

यह भारत और विश्वभर के लाखों स्वयंसेवकों के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। हम स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमारे पास मोहन भागवत जी जैसे दूरदर्शी और परिश्रमी सरसंघचालक हैं, जो ऐसे समय में संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं। एक युवा स्वयंसेवक से लेकर सरसंघचालक तक की उनकी जीवन यात्रा उनकी निष्ठा और वैचारिक दृढ़ता को दर्शाती है। विचार के प्रति पूर्ण समर्पण और व्यवस्थाओं में समयानुकूल परिवर्तन करते हुए उनके नेतृत्व में संघ कार्य का निरंतर विस्तार हो रहा है।

मैं मां भारती की सेवा में समर्पित मोहन भागवत जी के दीर्घ और स्वस्थ जीवन की पुनः कामना करता हूं। उन्हें जन्मदिवस पर अनेकानेक शुभकामनाएं। ■

(लेखक भारत के प्रधानमंत्री हैं)

प्रधानमंत्री तियानजिन (चीन) में 25वें एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल हुए

आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अगस्त से 1 सितम्बर, 2025 तक चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद् की 25वीं बैठक में भाग लिया। शिखर सम्मेलन में एससीओ विकास रणनीति, वैश्विक शासन में सुधार, आतंकवाद-निरोध, शांति और सुरक्षा, आर्थिक और वित्तीय सहयोग तथा स्थायी विकास पर उपयोगी चर्चा हुई।

शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एससीओ ढांचे के अंतर्गत सहयोग को मज़बूत करने के भारत के दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला। इस संबंध में उन्होंने कहा कि भारत तीन स्तंभों—सुरक्षा, संपर्क और अवसर के तहत व्यापक कार्य करना चाहता है। शांति, सुरक्षा और स्थिरता को प्रगति और समृद्धि की कुंजी बताते हुए श्री मोदी ने सदस्य देशों से आतंकवाद के सभी रूपों से लड़ने के लिए दृढ़ और निर्णायक कार्रवाई करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के वित्तपोषण और कट्टरपंथ के खिलाफ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद सदस्य देशों की मज़बूत एकजुटता के लिए धन्यवाद देते हुए उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि आतंकवाद से निपटने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए और समूह से आग्रह किया कि वह सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने वाले देशों को जवाबदेह ठहराएं।

भारत का चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसी परियोजनाओं का पुरज़ोर समर्थन

विकास को बढ़ावा देने और विश्वास निर्माण में कनेक्टिविटी की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे जैसी परियोजनाओं का पुरज़ोर समर्थन करता है। उन्होंने स्टार्ट-अप, नवाचार, युवा सशक्तीकरण और साझा विरासत के क्षेत्रों में अवसरों की भी चर्चा की, जिन्हें एससीओ के अंतर्गत आगे बढ़ाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लोगों के बीच बेहतर संबंधों और सांस्कृतिक समझ को बढ़ावा देने के लिए समूह के भीतर एक सभ्यतागत संवाद मंच शुरू करने का प्रस्ताव रखा।

श्री मोदी ने समूह के सुधारोन्मुखी एजेंडे के प्रति समर्थन व्यक्त किया। इस संबंध में उन्होंने संगठित अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी और साइबर सुरक्षा से निपटने के लिए केन्द्रों की स्थापना का स्वागत किया। श्री मोदी ने समूह से संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय संस्थाओं में सुधार के लिए भी इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान किया।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए बधाई दी। उन्होंने एससीओ की अगली अध्यक्षता संभालने पर किर्गिज़स्तान को भी बधाई दी। शिखर सम्मेलन के समापन पर एससीओ सदस्य देशों ने तियानजिन घोषणा को अपनाया।

शिखर सम्मेलन के दौरान द्विपक्षीय वार्ता

प्रधानमंत्री ने रूस के राष्ट्रपति से की मुलाकात

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक सितंबर को चीन के तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के दौरान रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने आर्थिक, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों सहित द्विपक्षीय सहयोग पर चर्चा की और इन क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में घनिष्ठता पर संतोष व्यक्त किया।

दोनों नेताओं ने यूक्रेन से जुड़े हाल ही के घटनाक्रमों सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने यूक्रेन

में संघर्ष के समाधान के लिए हाल ही में की गई पहलों के प्रति अपने समर्थन को दोहराते हुए संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने तथा एक स्थायी शांति समझौते की आवश्यकता पर बल दिया।

दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने कहा कि वह इस वर्ष के अंत में भारत में आयोजित 23वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति श्री पुतिन का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं।

प्रधानमंत्री की चीन के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अगस्त, 2025 को तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के नेताओं के शिखर सम्मेलन के अवसर पर चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से मुलाकात की।

दोनों नेताओं ने अक्टूबर, 2024 में कज़ान में अपनी पिछली बैठक के बाद से द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति और निरंतर प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि दोनों देश विकास साझेदार हैं, प्रतिद्वंद्वी नहीं और उनके मतभेद विवादों में नहीं बदलने चाहिए। भारत और चीन तथा उनके 2.8 अरब लोगों के बीच परस्पर सम्मान, आपसी हित और परस्पर संवेदनशीलता के आधार पर एक स्थिर संबंध और सहयोग दोनों देशों की वृद्धि और विकास के साथ-साथ 21वीं सदी के रुझानों के अनुरूप एक बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया के लिए आवश्यक है।

प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द के महत्व को रेखांकित किया। दोनों नेताओं ने पिछले वर्ष सफल सैन्य वापसी और उसके बाद से सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सौहार्द बनाए रखने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने अपने समग्र द्विपक्षीय संबंधों और दोनों देशों के लोगों के दीर्घकालिक हितों के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से सीमा संबंधित मुद्दों के निष्पक्ष, उचित और पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने इस महीने के आरंभ में दोनों विशेष प्रतिनिधियों द्वारा अपनी वार्ता में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकार किया तथा उनके प्रयासों को और समर्थन देने पर सहमति व्यक्त की।

दोनों नेताओं ने कैलाश मानसरोवर यात्रा और पर्यटक वीजा की बहाली के आधार पर सीधी उड़ानों और वीजा सुविधा के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। आर्थिक और व्यापारिक संबंधों के संदर्भ में उन्होंने विश्व व्यापार को स्थिर करने में अपनी दोनों अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों का विस्तार करने तथा व्यापार घाटे को कम करने के लिए एक राजनीतिक और कार्यनीतिक दिशा में आगे बढ़ने की आवश्यकता पर बल दिया।

भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं: नरेन्द्र मोदी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि भारत और चीन दोनों ही रणनीतिक स्वायत्तता चाहते हैं और उनके संबंधों को किसी तीसरे देश के दृष्टिकोण से नहीं देखा जाना चाहिए। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों पर आतंकवाद और निष्पक्ष व्यापार जैसे द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों एवं चुनौतियों पर साझा आधार का विस्तार करना आवश्यक समझा।

प्रधानमंत्री ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की चीन की अध्यक्षता और तियानजिन में शिखर सम्मेलन के लिए समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने राष्ट्रपति श्री शी को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया, जिसकी मेजबानी भारत 2026 में करेगा। राष्ट्रपति श्री शी ने निमंत्रण के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया और भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन की पेशकश की। ■

भारत-जापान ने विशेष रणनीतिक तथा वैश्विक साझेदारी को और मजबूत करने पर की रचनात्मक चर्चा

जापान के प्रधानमंत्री श्री इशिबा शिगेरु के निमंत्रण पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15वें भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए 29-30 अगस्त, 2025 को जापान की आधिकारिक यात्रा की। प्रधानमंत्री श्री मोदी का 29 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय (कांतेई) में प्रधानमंत्री श्री इशिबा ने स्वागत किया, जहां उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान भारत और जापान के बीच दीर्घकालिक मित्रता को याद किया जो सभ्यतागत संबंधों, साझा मूल्यों और हितों, समान रणनीतिक दृष्टिकोण और एक-दूसरे के प्रति पारस्परिक सम्मान में निहित हैं। दोनों प्रधानमंत्रियों ने पिछले दशक में भारत-जापान साझेदारी द्वारा की गई महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की और आने वाले दशकों में पारस्परिक सुरक्षा और समृद्धि के लिए रणनीतिक और दूरंदेशी साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर रचनात्मक चर्चा की।

दोनों प्रधानमंत्रियों ने दोनों पक्षों के बीच निरंतर उच्च-स्तरीय आदान-प्रदान तथा मंत्रिस्तरीय एवं संसदीय सहभागिता का स्वागत किया, जो आपसी विश्वास और संबंधों की गहराई को दर्शाता है। पिछले एक दशक में यह साझेदारी सुरक्षा, रक्षा, व्यापार, निवेश, वाणिज्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कौशल एवं गतिशीलता तथा सांस्कृतिक एवं लोगों के बीच संबंधों जैसे व्यापक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण ढंग से बढ़ी है।

प्रधानमंत्री की जापान यात्रा के परिणामों के प्रमुख बिंदु

अगले दशक के लिए भारत-जापान संयुक्त दृष्टिकोण

आर्थिक साझेदारी, आर्थिक सुरक्षा, गतिशीलता, टिकाऊ पारिस्थितिकी, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्वास्थ्य, लोगों के बीच आपसी संपर्क और दोनों देशों के बीच आपसी संपर्क जैसे आठ क्षेत्रों में आर्थिक और कार्यात्मक सहयोग के लिए 10-वर्षीय रणनीतिक प्राथमिकता।

सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा

हमारी विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के अनुरूप समकालीन सुरक्षा चुनौतियों का सामना करने के लिए हमारे रक्षा और सुरक्षा सहयोग को विकसित करने की दिशा में एक व्यापक ढांचा तैयार करना।

भारत-जापान मानव संसाधन आदान-प्रदान हेतु कार्य योजना

अगले पांच वर्षों में भारत और जापान के बीच 5,00,000 लोगों, विशेष रूप से भारत से जापान के लिए 50,000 कुशल और अर्ध-कुशल कर्मियों के आपसी आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार करना।

भारत-जापान डिजिटल साझेदारी 2.0 पर समझौता ज्ञापन

डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे, डिजिटल प्रतिभा के विकास और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) और सेमीकंडक्टर जैसे भविष्य के तकनीकी क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान एवं विकास में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने हेतु एक दस्तावेज़।

अन्य उल्लेखनीय परिणाम

- अगले दशक के लिए जापान से भारत में 10 ट्रिलियन जापानी येन का निजी निवेश का लक्ष्य।
- भारत और जापान ने सेमीकंडक्टर, स्वच्छ ऊर्जा, दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स, महत्वपूर्ण खनिजों के साथ-साथ नई और उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आपूर्ति श्रृंखला के अनुकूलन को प्रोत्साहन देने के लिए आर्थिक सुरक्षा पहल शुरू की।
- बुनियादी ढांचे, लॉजिस्टिक्स और मोबिलिटी क्षेत्रों, विशेष रूप से रेलवे, विमानन, सड़क, शिपिंग और बंदरगाहों में जी2जी और बी2बी साझेदारी को बढ़ावा देना, जिसमें मोबिलिटी उत्पादों और समाधानों के मेक-इन-इंडिया पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ■

अप्रैल-जून, 2025 के दौरान वास्तविक जीडीपी में 7.8 प्रतिशत की हुई भारी वृद्धि

वास्तविक निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई थी

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा 29 अगस्त को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीडीपी या स्थिर मूल्यों पर अनुमानित जीडीपी 47.89 लाख करोड़ रुपए है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह 44.42 लाख करोड़ रुपए थी, जो 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी 86.05 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह 79.08 लाख करोड़ रुपए थी, जो 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाती है।

वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में वास्तविक जीवीए 44.64 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह 41.47 लाख करोड़ रुपए था, जो 7.6 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में जीवीए 78.25 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह 71.95 लाख करोड़ रुपए था, जो 8.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्शाता है।

मुख्य बातें

- कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में वास्तविक जीवीए वृद्धि दर 3.7 प्रतिशत रही, जबकि पिछले वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई थी।
- द्वितीयक क्षेत्र, प्रमुख रूप से विनिर्माण (7.7 प्रतिशत) और निर्माण (7.6 प्रतिशत) क्षेत्र ने इस तिमाही में स्थिर मूल्यों पर 7.5 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर दर्ज की है।
- खनन और उत्खनन (-3.1 प्रतिशत) और बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगिता सेवा क्षेत्र (0.5 प्रतिशत) में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान वास्तविक विकास दर में कमी देखी गई है।
- तृतीयक क्षेत्र (9.3 प्रतिशत) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में स्थिर मूल्यों पर पर्याप्त वृद्धि दर दर्ज की है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.8% की वृद्धि दर दर्ज की गई थी।
- सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान 9.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में यह वृद्धि दर 4.0 प्रतिशत थी।
- वास्तविक निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही के दौरान 7.0 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई थी।
- सकल स्थिर पूंजी निर्माण (जीएफसीएफ) ने स्थिर मूल्यों पर 7.8 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की है, जबकि वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6.7 प्रतिशत की वृद्धि दर दर्ज की गई थी। ■

पीएम स्वनिधि योजना के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने को मिली मंजूरी

पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 अगस्त को 'प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना' के पुनर्गठन और ऋण अवधि को 31 दिसंबर, 2024 से आगे बढ़ाने को मंजूरी दी। यह ऋण अवधि अब 31 मार्च, 2030 तक बढ़ा दी गई है। इस योजना का कुल परिव्यय 7,332 करोड़ रुपए है। पुनर्गठित योजना का लक्ष्य 50 लाख नए लाभार्थियों सहित 1.15 करोड़ लाभार्थियों को लाभ देना है।

पुनर्गठित योजना की प्रमुख विशेषताओं में पहली और दूसरी किस्त में बढ़ी हुई ऋण राशि, दूसरा ऋण चुकाने वाले लाभार्थियों के लिए यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड का प्रावधान और खुदरा एवं थोक लेनदेन के लिए डिजिटल कैशबैक प्रोत्साहन शामिल हैं। इस योजना का दायरा चरणबद्ध तरीके से जनगणना कस्बों व अर्ध-शहरी क्षेत्रों आदि बढ़ाया जा रहा है।

उन्नत ऋण संरचना में प्रथम किश्त के ऋण को 15,000 रुपए (10,000 रुपए से) तक बढ़ाया गया है तथा द्वितीय किश्त के ऋण को 25,000 रुपए (20,000 रुपए से) तक बढ़ाया गया है, जबकि तृतीय किश्त पहले की तरह 50,000 रुपए पर है।

यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत से स्ट्रीट वेंडरों को किसी भी आकस्मिक व्यावसायिक और व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल ऋण उपलब्ध हो सकेगा।

इसके अलावा, डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रीट वेंडर खुदरा और थोक लेनदेन करने पर 1,600 रुपए तक के कैशबैक प्रोत्साहन का लाभ उठा सकते हैं। ■

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना युवा शक्ति के सपनों को देगी नई उड़ान

डॉ. मनसुख मांडविया

भारत की विकास गाथा हमेशा से उसकी श्रम शक्ति द्वारा लिखी गई है। देश की अर्थव्यवस्था को गति देने में करोड़ों श्रमिकों के समर्पण और क्षमता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2014 में भारत विश्व की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ते हुए आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। भारत ने वैश्विक पटल पर अपने लिए एक उल्लेखनीय स्थान बनाया है और इसमें इसके मानव संसाधन की शक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

इस सफलता की कहानी को बल देने वाला तथ्य यह है कि भारत के आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। आरबीआई-केएलईएमएस के अनुसार, जहां 2004-2014 के बीच केवल 2.9 करोड़ रोजगार सृजित हुए थे, उसके बाद के दशक में 17 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित हुए। औपचारिकीकरण में भी तेजी आई है, ईपीएफओ के आंकड़ों के अनुसार पिछले सात वर्षों में लगभग आठ करोड़ नौकरियां सृजित हुई हैं।

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में बढ़ोतरी होना भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। 2015 में केवल 19 प्रतिशत भारतीय कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते थे। 2025 तक यह संख्या बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो चुकी है और 94 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में आए हैं, जिससे भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने वाला देश बन गया है। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस उपलब्धि को वैश्विक स्तर पर कवरेज के सबसे तेज विस्तार में से एक माना है।

यह स्पष्ट है कि राष्ट्र का भविष्य न केवल जीडीपी वृद्धि की गति से, बल्कि हमारे द्वारा सृजित नौकरियों की गुणवत्ता, श्रमिकों को दी जाने वाली सुरक्षा और अपने युवाओं को प्रदान किए जाने वाले अवसरों से भी तय होगा। बढ़ते स्वचालन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कारण बनी अनिश्चितता की स्थिति, आपूर्ति-श्रृंखला में बदलाव और दुनिया भर में नौकरियों को आकार देने वाली कई अन्य कमजोरियों की वैश्विक पृष्ठभूमि में भारत एक जनसांख्यिकीय परिवर्तन के बिंदु पर खड़ा है।

> **भारत में सामाजिक सुरक्षा कवरेज में बढ़ोतरी होना भी हमारी एक बड़ी उपलब्धि है। 2015 में केवल 19 प्रतिशत भारतीय कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते थे। 2025 तक यह संख्या बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो चुकी है और 94 करोड़ लाभार्थी इसके दायरे में आए हैं, जिससे भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा कवरेज देने वाला देश बन गया है**

हमारी 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो एक महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभांश है, जो हमारी अर्थव्यवस्था को गति दे देता है, जबकि पश्चिमी देशों में आबादी वृद्ध होती हो रही है। वर्षों से भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश यानी इसकी युवा शक्ति को इसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता रहा है। फिर भी, पिछली सरकारों के अधीन इस क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया। अमृत काल में जब हम 2047 तक एक विकसित भारत के विजन की दिशा में प्रयास कर रहे हैं, हमारे सामने कार्य स्पष्ट है: हमें 'संभावना' से 'समृद्धि' की ओर बढ़ना होगा।

इस पृष्ठभूमि में रोजगार अब केवल एक आर्थिक संकेतक नहीं रह गया है; यह सम्मान, समानता और राष्ट्रीय शक्ति का आधार है। इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने युवाओं को रोजगार योग्य बनाएं, उन्हें औपचारिक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करें, उन्हें वित्तीय साक्षरता से लैस करें और यह सुनिश्चित करें कि वे एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित हों। तभी हमारा जनसांख्यिकीय लाभ वास्तव में एक स्थायी राष्ट्रीय लाभांश में परिवर्तित हो सकता है।

इसी चुनौती का समाधान करने और आकांक्षा व अवसर के बीच के अंतर को पाटने के लिए, 15 अगस्त को लाल क़िले प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की है। वास्तव में केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रस्तुत और प्रधानमंत्री जी के अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस संबोधन में घोषित यह योजना पैमाने और डिजाइन, दोनों ही दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती है। 1 लाख करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ यह भारत के इतिहास का सबसे महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है, जिससे 3.5 करोड़ से ज़्यादा रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। इनमें से दो करोड़

लाभार्थी पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे।

योजना के दो स्तंभ: पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को प्रोत्साहन और नियोक्ताओं को सहायता

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को इसकी संरचना ही अलग बनाती है। रोजगार सृजन को बढ़ावा देने वाले पहले के कार्यक्रमों के विपरीत, यह योजना युवाओं की रोजगार क्षमता और उद्यम प्रतिस्पर्धात्मकता की दोहरी चुनौती का एक साथ समाधान करती है। भाग 'ए' के तहत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों (दो किश्तों में 15,000 रुपए तक) और भाग 'बी' के तहत नियोक्ताओं (प्रत्येक नए कर्मचारी के लिए प्रति माह 3,000 रुपए तक) को प्रत्यक्ष वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके, यह श्रमिकों के लिए प्रवेश बाधाओं को कम करता है और साथ ही व्यवसायों के लिए नियुक्ति जोखिम को भी कम करता है।

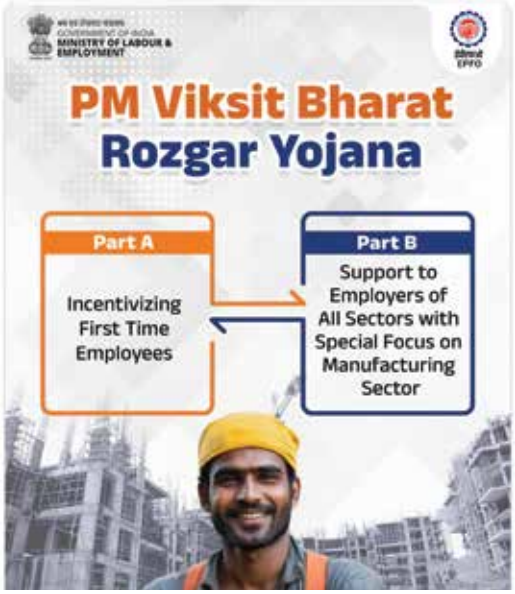

इस योजना का औपचारिकीकरण और सामाजिक सुरक्षा एकीकरण की दिशा में प्रोत्साहन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रदान किए जाएंगे, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नए कर्मचारियों को पहले दिन से ही सामाजिक सुरक्षा प्रणालियों से जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, एक औपचारिक, सुरक्षित और उत्पादक श्रम बाजार की ओर एक संरचनात्मक कदम है। इसके अलावा, विनिर्माण क्षेत्र में नियोक्ताओं को प्रोत्साहन पर अतिरिक्त ध्यान, भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और प्रयास है।

समावेशी और सतत विकास को गति देना

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, योजना-आधारित पहलों से हटकर एक व्यापक रोजगार प्रणाली की ओर बदलाव का संकेत देती है। यह पूर्व की पहलों से मिली सीख पर आधारित है, उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई), राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन और मेक इन इंडिया जैसी वर्तमान योजनाओं का पूरक है और प्रतिस्पर्धी वैश्विक व्यवस्था में काम की बदलती प्रकृति को पहचानती है।

श्रमिकों और नियोक्ताओं, दोनों को प्रोत्साहन देकर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना यह मान्यता देती है कि रोजगार सृजन एक साझा जिम्मेदारी है। भारत डिजिटल नवाचार को अपनाते हुए एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का प्रयास कर रहा है, इसलिए यह योजना सुनिश्चित करती है कि कोई भी पीछे न छूटे - यहां तक कि सबसे छोटा उद्यम और कार्यबल में शामिल होने वाला सबसे नया व्यक्ति भी राष्ट्रीय विकास की यात्रा में भागीदार बने।

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना: नए भारत की नींव

प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना एक नीतिगत घोषणा से कहीं अधिक बढ़कर है। यह जनसांख्यिकीय लाभांश को सार्वजनिक समृद्धि में बदलने की दिशा में एक ठोस कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में यह पहल विकसित भारत के विजन को साकार करने की नींव का हिस्सा है, जहां हर युवा को सार्थक रोजगार मिले, हर काम में सम्मान हो और हर युवा को अपने सपनों को साकार करने का अवसर मिले।

रोजगार निर्माण सही मायने में राष्ट्र निर्माण है। इस पहल के साथ मोदी सरकार अपनी इस प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रही है कि कोई भी आकांक्षा अधूरी नहीं रहेगी और कोई भी युवा अवसर से वंचित नहीं रहेगा। हम सब मिलकर भारत की युवा शक्ति को नई उड़ान दे रहे हैं और उनके माध्यम से विकसित भारत के सपने को भी नई गति प्रदान कर रहे हैं। ■

(लेखक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री हैं)

कमल संदेश परिवार की ओर से
सुधी पाठकों को
नवरात्रि (22 सितम्बर)
की हार्दिक शुभकामनाएं!

जीएसटी कटौती 2025

मजबूत विकास के लिए जन-केंद्रित सुधार

अरुण सिंह

मोदी सरकार ने जीएसटी व्यवस्था को सरल और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। जीएसटी परिषद् और वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित ऐतिहासिक जीएसटी सुधार, जो 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे, ने कर ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। विभिन्न टैक्स स्लैबों को अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों (शून्य एवं उच्चतर अवगुण उत्पादों पर लगने वाली दरों के साथ) के तहत लाया गया है, यह सुधार सैकड़ों रोजमर्रा की वस्तुओं और प्रमुख उत्पादों पर इनपुट कर का बोझ कम करेगा, जबकि विलासिता और अहितकर वस्तुओं पर उच्च दरें लागू होंगी। इन उपायों का स्पष्ट उद्देश्य आम लोगों पर बोझ कम करना, उपभोग को प्रोत्साहित करना, घरेलू विनिर्माण और निर्यात को नुकसान पहुंचाने वाले शुल्क ढांचों को ठीक करना और अनुपालन को सरल बनाना है।

इस प्रक्रिया में एक बड़ा कदम स्लैबों का एकीकरण रहा, जिसके तहत अब ज्यादातर वस्तुओं एवं सेवाओं को 12 प्रतिशत या 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत की दर के तहत लाया गया है। जरूरी खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा के इस्तेमाल वाले एफएमसीजी उत्पादों को काफी कम दरों पर रखा गया और कुछ वस्तुओं पर तो शून्य कर भी लागू किया गया है, जिसमें साधारण ब्रेड और कुछ पैकेज्ड डेयरी उत्पाद शामिल हैं।

एक और महत्वपूर्ण कदम विभिन्न कंज्यूमर ड्यूरेबल और मोबिलिटी श्रेणियों के लिए कर दरों में कमी करना था। जिन वस्तुओं पर पहले 28 प्रतिशत जीएसटी लगता था, जैसे चुनिंदा एयर कंडीशनर, 32 इंच तक के टेलीविजन, डिशवॉशर, छोटी कारें और 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलें, उन्हें घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया गया। कृषि मशीनीकरण और ग्रामीण उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी पर भी कम दरें लागू की गईं।

इस सुधार ने लंबे समय से लंबित इनवर्टेड ड्यूटी ढांचे के मुद्दे को भी संबोधित किया। मानव निर्मित रेशे और धागों को कम दरों पर लाया गया, जिससे कपड़ा क्षेत्र में प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा और निर्यात की संभावनाओं को बल मिलेगा। हस्तशिल्प और सांस्कृतिक वस्तुओं को भी कम दरों के माध्यम से राहत मिली है, जिससे कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को संरक्षण एवं समर्थन मिलेगा।

> **जीएसटी परिषद् और वित्त मंत्रालय द्वारा घोषित ऐतिहासिक जीएसटी सुधार, जो 22 सितंबर, 2025 से प्रभावी होंगे, ने कर ढांचे में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। विभिन्न टैक्स स्लैबों को अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दरों (शून्य एवं उच्चतर अवगुण उत्पादों पर लगने वाली दरों के साथ) के तहत लाया गया है**

यह सभी उपाय लागू होने पर उपभोक्ता कीमतों को स्रोत पर ही कम करेंगे तथा उन विकृतियों को दूर करेंगे, जो पहले घरेलू मूल्य संवर्धन और विनिर्माण को हतोत्साहित करती थीं।

एक नीतिगत उपलब्धि

जीएसटी सुधार आम लोगों और छोटे उपभोक्ताओं के पक्ष में एक बड़े झुकाव को दर्शाता है। आवश्यक वस्तुओं पर दरें कम करके सरकार ने एक स्पष्ट कल्याणकारी कदम उठाया है जो निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों पर कर का बोझ कम करेगा। इस निर्णय के बाद वस्तुओं की खुदरा कीमतों में सीधे तौर पर कमी आयेगी, जिससे नागरिकों को भारी राहत मिलेगी।

अब सुव्यवस्थित स्लैब संरचना भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। वर्गीकरण विवादों और अनुपालन संबंधी जटिलताओं को कम करके यह सुधार व्यवसायों की लागत कम करेंगे और साथ ही चालान-स्तर की सटीकता और ई-फाइलिंग दक्षता में सुधार होगा। उद्योग मंडलों ने पहले ही संकेत दे दिया है कि यह सरलीकरण अनुपालन संबंधी बाधाओं को कम करेगा और दीर्घकालिक राजस्व स्थिरता को बढ़ावा देगा।

इस सुधार में एक मजबूत रणनीतिक औद्योगिक नीतिगत आयाम भी निहित है। कपड़ा, हस्तशिल्प, उर्वरक और कृषि मशीनरी में इनवर्टेड ड्यूटी ढांचे को ठीक करने से यह सुनिश्चित होता है कि कर नीति निर्यात प्रतिस्पर्धा, ग्रामीण आजीविका और कृषि उत्पादकता जैसे राष्ट्रीय उद्देश्यों के साथ बेहतर ढंग से संरेखित हो। ये लक्षित सुधार अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को मजबूत करते हैं और कारीगरों जैसे कमज़ोर वर्गों की रक्षा करते हैं।

इस सुधार का राजनीतिक परिदृश्य पर स्पष्ट प्रभाव पड़ेगा। इसकी पुनर्वितरणात्मक प्रकृति किसी वस्तु की बिक्री के समय आसानी से देखी जा सकती है, जिससे यह एक प्रमुख नीतिगत उपलब्धि बन जाती है, जो जनता के साथ जुड़ती है। रोजमर्रा की लागत कम करके और सभी क्षेत्रों में मांग को

बढ़ावा देकर यह सुधार न केवल नागरिकों के कल्याण को समर्थन करता है, बल्कि व्यापक आर्थिक विकास को गति देने में सरकार की विश्वसनीयता को भी मजबूत करता है।

लघु से मध्यम अवधि के आर्थिक प्रभाव, साक्ष्य और अनुमान

जीएसटी दरों में कटौती से आने वाली तिमाहियों में खपत को बढ़ावा मिलने और जीडीपी वृद्धि में तेज़ी आने की व्यापक उम्मीद है। कई विश्लेषकों और उद्योग अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया है कि यह सुधार मांग को बढ़ावा देगा। विभिन्न अर्थशास्त्रियों के शुरुआती अनुमानों के अनुसार वित्त वर्ष की दूसरी छमाही और वित्त वर्ष 27 में इसके सकारात्मक प्रभाव देखे जा सकते हैं। कम जीएसटी दरों से परिचालन दक्षता में सुधार होगा और औपचारिक बाजार का विस्तार होगा, जिससे विकास को गति मिलेगी।

हालांकि, वास्तविक उपभोग वृद्धि कर कटौती का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाने पर निर्भर करती है। कई वाहन निर्माता और उपभोक्ता वस्तु कंपनियां पहले ही घोषणा कर चुकी हैं कि वे इसका लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाएंगी। मीडिया रिपोर्ट्स इस बात की पुष्टि करती हैं कि कुछ कंपनियों ने वाहनों और दोपहिया वाहनों की कीमतों में संशोधन किया है, जो इस बात का संकेत है कि इस सुधार का उपभोक्ताओं को ठोस मूल्य राहत मिल रही है।

क्षेत्रीय मांग के संकेत भी उभर रहे हैं। उदाहरण के लिए, टायर निर्माता और ट्रैक्टर कलपुर्जे आपूर्तिकर्ता, ज़्यादा उत्पादन की उम्मीद कर रहे हैं। प्रमुख टायर कंपनी सिएट ने ट्रैक्टर और शुरुआती स्तर के मोटरसाइकिल टायरों की मांग में वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो कर कटौती के बाद ग्रामीण और आम बाजार में बढ़ती मांग का एक प्रारंभिक संकेत है।

साथ ही, राजकोषीय कमी को भी स्वीकार किया जाना चाहिए। स्वतंत्र शोध और कर सलाहकार विश्लेषणों का अनुमान है कि संभावित राजस्व हानि सालाना 70,000 करोड़ रुपये से 1.8 लाख करोड़ रुपये के बीच होगी। इसका अंतिम प्रभाव उपभोग, अनुपालन लाभों के माध्यम से औपचारिक आधार के विस्तार और राज्य क्षतिपूर्ति तंत्र की प्रभावशीलता जैसे कारकों पर निर्भर करेगा। केंद्र-राज्य राजकोषीय संतुलन बनाए रखने और मध्यम अवधि के बजट तैयार करने के लिए राजस्व का यह आयाम महत्वपूर्ण है।

क्षेत्रीय कल्याण और लाभ विश्लेषण

जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने से फास्ट-मूविंग उपभोक्ता वस्तुओं, घरेलू वस्तुओं और खाद्य पदार्थों में महत्वपूर्ण कल्याणकारी बदलाव होंगे। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट, पैकेज्ड स्नैक्स, स्टेपल और चुनिंदा डेयरी उत्पादों पर कम कर उपभोक्ताओं के दैनिक खर्च को कम करेगी। इसका एक प्रगतिशील प्रभाव पड़ता है क्योंकि निम्न-आय वाले परिवार अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा इन वस्तुओं पर खर्च करते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी वास्तविक क्रय शक्ति बढ़ेगी। अल्पावधि में इस नीति से बिक्री में वृद्धि और अनौपचारिक खुदरा विक्रेताओं के लिए मार्जिन में कमी आने की उम्मीद है, जबकि मध्यम अवधि में यदि मूल्य में कमी जारी रहती है, तो यह पोषण और स्वच्छता के बेहतर परिणामों में योगदान दे सकती है।

कृषि, ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी के लिए कम जीएसटी सीधे तौर पर किसानों की लागत कम करता है और मशीनीकरण को बढ़ावा देता है। इसका कल्याणकारी प्रभाव कृषि उत्पादकता में वृद्धि, शारीरिक श्रम में कमी और उपकरणों के व्यापक उपयोग से बेहतर ग्रामीण आय के रूप में स्पष्ट है

ऑटोमोबाइल और दोपहिया वाहन क्षेत्र में कुछ वस्तुओं पर कर दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत की गयी है, साथ ही 350 सीसी तक की मोटरसाइकिलों पर छूट दी गयी है, जो उत्पादन लागत को कम करता है। इससे पहली बार खरीदारी करने वालों, ग्रामीण यात्रियों और छोटे पैमाने के परिवहन संचालकों के लिए सामर्थ्य में सुधार होगा, जिससे श्रम बाजार में गतिशीलता को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग जगत की प्रतिक्रियाएं पहले से ही निकट भविष्य में कीमतों में सुधार और मात्रा में वृद्धि का संकेत दे रही हैं, हालांकि यह जोखिम बना हुआ है कि अगर मांग बहुत तेज़ी से बढ़ती है, तो आपूर्ति शृंखला की बाधाएं पूरे लाभ को कम कर सकती हैं।

कृषि, ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी के लिए कम जीएसटी सीधे तौर पर किसानों की लागत कम करता है और मशीनीकरण को बढ़ावा देता है। इसका कल्याणकारी प्रभाव कृषि उत्पादकता में वृद्धि, शारीरिक श्रम में कमी और उपकरणों के व्यापक उपयोग से बेहतर ग्रामीण आय के रूप में स्पष्ट है। यह बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गुणक प्रभाव उत्पन्न करता है। सिएट सहित निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं ने पहले ही ट्रैक्टर टायरों की मांग में वृद्धि का अनुमान लगा लिया है, जो ग्रामीण मांग में मजबूती का संकेत है।

मानव निर्मित रेशों और हस्तशिल्प के साथ-साथ कपड़ा क्षेत्र को भी इनवर्टेड ड्यूटी ढांचे में सुधार का लाभ मिला है, जिससे पहले इनपुट लागत बढ़ जाती थी। इनपुट पर करों में कमी और हस्तशिल्प के लिए दरें कम करके यह सुधार घरेलू मूल्य शृंखलाओं को मज़बूत करता है, निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार करता है और कारीगरों की आजीविका को सहारा देता है। इससे एमएसएमई के लिए बेहतर मार्जिन और श्रम-प्रधान क्षेत्रों में संभावित रोज़गार वृद्धि हो सकती है।

स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहे हैं, कुछ चिकित्सा उत्पादों, स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं और पैकेज्ड स्टेपल पर दरें कम की जा रही है। ये बदलाव सामर्थ्य में सुधार लाते

शेष पृष्ठ 34 पर...

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस (14 अगस्त) पर विशेष

भारत का दर्द, भारत का संकल्प

तरुण चुग

गतांक का शेष...

विभाजन की स्मृति पंजाब के सामूहिक चित्त में आज भी उतनी ही गहराई से बनी हुई है। जिन परिवारों ने सब कुछ खो दिया, उन्होंने यूं ही 'आगे बढ़कर भूल जाओ' नहीं कर दिया – हां, उन्होंने नए सिरे से जीवन जरूर खड़ा किया, लेकिन अपने अतीत को सीने में संजोकर रखा। वे उस शहर या गांव का नाम मरते दम तक जिह्वा पर रखते रहे, जो पीछे छूटा था – लोकगीतों में, लोरियों में, उनके पकवानों के ज़ायकों में, उनकी दुआओं में वह ज़िक्र ज़िंदा रहा। भला भूलते भी कैसे? जिस मां की नज़र के सामने उसकी औलाद मार दी गई हो, वह कैसे भूल सकती है? जिस दादा ने 'भूतिया ट्रेन' में अमृतसर पहुंचकर अपने पूरे परिवार को खोया हो, वह क्या ख़ाक भूल पाएगा? जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर यह सफ़र काटा, उन्होंने इंसानियत का नर्क भी देखा और उसका उजाला भी। उन्होंने कुछ पागल उन्मादियों को वहशीपन पर उतरते देखा, तो दूसरे अजनबियों को अपनी जान जोख़िम में डालकर दूसरों को बचाते भी देखा। दरअसल, भयानक खूनी हिंसा के बीच असंख्य मिसालें इंसानियत की भी दिखीं – किसी हिन्दू पड़ोसी ने अंतिम क्षणों में अपने मुस्लिम दोस्त का परिवार छिपा लिया और बचा दिया; किसी सिख किसान ने आसपास के मुसलमान गांवों को हथियारबंद गिरोहों से सुरक्षा दी; अनजाने हिंदू परिवारों ने अपनी बची-खुची रोटियां भूखे मुसाफ़िरों में बांट दीं। पंजाब हमें ये सीख देता है कि अलग-अलग मज़हबों और जातियों का मिलकर रहना अनमोल है, लेकिन नाज़ुक भी है और एक बार अगर अविश्वास का बीज बो दिया जाए तो भड़की नफ़रत की आग में हम सब जलते हैं, कोई नहीं बचता। विभाजन का दर्द, जिसे 1947 में भारत के पंजाब एवं बंगाल को बांटकर हम पर थोपा गया, ने भारत की आत्मा पर गहरा घाव बना दिया। वह घाव एक चेतावनी है कि हम फिर कभी ऐसे ज़हर को अपने समाज में मत पनपने दें।

जहां पश्चिम में पंजाब बंटवारे का सबसे बड़ा रणक्षेत्र बना, वहीं पूरब में बंगाल भी लहूलुहान हुआ। रैडक्लिफ़ रेखा ने पूर्व में बंगाल को दो टुकड़ों में काट दिया – पश्चिम बंगाल भारत में रहा और पूर्वी बंगाल, जो आगे चलकर पूर्वी पाकिस्तान बना। पंजाब की तरह ही, बंगाल का बंटवारा भी अचानक, बिना तैयारी के और निर्दयता से लागू किया गया। कोलकाता जैसे चहल-पहल से भरे शहर शरणार्थियों के विशाल शिविरों में बदल गए, जहां पूर्वी बंगाल के कस्बों और गांवों से दंगों और लक्षित हत्याओं से भागकर पहुंचे लाखों हिंदू आश्रय लेने लगे। नोआखाली और टिपेरा में आज़ादी से पहले ही पूरे के पूरे हिंदू गांव उजाड़ दिए गए थे, जिससे लोग अपना घर-बार छोड़कर भागने को मजबूर हुए। सदियों से व्यापार और संस्कृति की धड़कन रही बंगाल की नदियां अब भागते हुए परिवारों की जीवनरेखा बन गईं। नावों, बैलगाड़ियों और पैदल – जैसे भी हो सके – लोग पार जाने लगे, लेकिन बहुत-से अपने प्रियजन रास्ते में हिंसा या कठिन यात्रा में खो बैठे।

> **विभाजन का दर्द, जिसे 1947 में भारत के पंजाब एवं बंगाल को बांटकर हम पर थोपा गया, ने भारत की आत्मा पर गहरा घाव बना दिया। वह घाव एक चेतावनी है कि हम फिर कभी ऐसे ज़हर को अपने समाज में मत पनपने दें**

बंगाल की त्रासदी का दर्द अलग तरह का था। यहां हिंसा अचानक भड़कती और फिर लंबे समय तक भय और अभाव का माहौल बना रहता। 1946 में कोलकाता और नोआखाली के सांप्रदायिक दंगे पहले ही सामाजिक ताने-बाने को चीर चुके थे। 1947 आते-आते वह अविश्वास एक विशाल पलायन में बदल गया। अगले कुछ वर्षों में 30 लाख से अधिक हिंदू पूर्वी बंगाल से भारत आए, जिससे पश्चिम बंगाल के शहर और गांव क्षमता से अधिक भर गए। कोलकाता, हावड़ा और सिलीगुड़ी के किनारों पर शरणार्थी शिविर उग आए, जहां न तो पर्याप्त स्वच्छता थी और न ही भोजन। पंजाब की तरह ही, बंगाल के विस्थापित अपने साथ सिर्फ़ शारीरिक घाव ही नहीं, बल्कि उजड़े घरों, अपवित्र किए गए मंदिरों और छूट चुकी पुश्तैनी ज़मीनों की पीड़ा भी लेकर आए। बंगाल का यह दर्द याद दिलाता है कि विभाजन कोई एक नहीं, बल्कि दो महाविपत्तियां थीं, जो भारतीय उपमहाद्वीप के दो सिरों पर अलग-अलग रूप में घटीं, पर मानव त्रासदी के बोझ में समान थीं।

इसी असहनीय पीड़ा की पराकाष्ठा को स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2021 में ऐलान किया कि अब से हर वर्ष 14 अगस्त को 'विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस' के रूप में मनाया जाएगा। सात दशक बाद आज़ाद भारत ने यह क़दम उठाया है तो यह महज़ सांकेतिक भर नहीं है। यह सच के सम्मान और श्रद्धांजलि का कार्य है। इतने वर्षों तक विभाजन के ज़िंदा बचे गवाहों की कहानियां घर-परिवार तक ही सिमटी रहीं या धुंधली चिट्ठियों में दफ़न रहीं। अब, इस दिन को औपचारिक स्मृति-दिवस घोषित करके हम उन कहानियों को राष्ट्रीय कथा-प्रवाह का हिस्सा बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने उचित ही कहा था, "विभाजन की पीड़ाएं कभी भुलाई नहीं जा सकतीं। नफ़रत और हिंसा के कारण लाखों बहनों-भाइयों को अपना घर छोड़ना पड़ा, कितनों ने अपनी जान

गंवाई।" उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि यह दिवस हम सभी को 'भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के ज़हर को ख़त्म करने की जरूरत' सतत याद दिलाए और समाज में एकता व सद्भावना की भावना को मज़बूत करे। इस तरह मानो प्रधानमंत्री ने वो बात कह दी जो हर हिंदुस्तानी अपने दिल में महसूस करता है: कि हमारी राष्ट्रीय एकता अनमोल भी है और बहुत मूल्य चुकाकर हासिल की गई है – 1947 के शहीदों के लहू से सींचकर मिली है। जब पूरे देश में आधिकारिक रूप से विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, तो ये हमारा अतीत के साथ किया गया एक वादा होता है – कि हम अपनी जनता के उस कष्ट को सम्मानपूर्वक याद रखेंगे और उन लाखों आत्माओं का बलिदान जिन्हें आज़ादी की सुबह देखने को नहीं मिली, उन्हें नमन करेंगे। यह हमारा भविष्य के साथ भी किया गया वादा है कि आने वाली हर पीढ़ी को हम बताएंगे कि साम्प्रदायिक नफ़रत का विष कितना प्रलयंकारी हो सकता है, ताकि वैसी भूल फिर दोहराई न जाए।

भारतीय जनता पार्टी के लिए और मेरे स्वयं के लिए भी, यह संकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। भाजपा सदैव 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के सिद्धांत पर चली है – जिसमें हमारे राष्ट्र की बहुलता में एकता को उत्सव की तरह मनाया जाता है और उसकी रक्षा को सर्वोपरि कर्तव्य माना जाता है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस इसी प्रतिबद्धता का हिस्सा है। यह सुनिश्चित करता है कि हम न अतीत को भुलाएं न उसके सबक़ों से आंख मूंदें। मैं स्वयं पंजाब की संतानों में से हूं और एक भारतीय होने के नाते बचपन से अपने घर में विभाजन की कहानियां सुनता आया हूं – बुज़ुर्गों की भर्राई आवाज़ों में वो दास्तानें सुनी हैं जिन्होंने वह क़हर अपनी आंखों देखा था। उन शहीदों और पीड़ितों के प्रति मैं गहरा कर्तव्यभाव महसूस करता हूं। हम भाजपा में यह कटिबद्ध हैं कि उन कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जाने देंगे, न ही उन्हें व्यर्थ जाने देंगे। विभाजन की विभीषिका को याद रखना हमारे लिए देश की एकता को मज़बूत करने का एक साधन है, क्योंकि इससे हम उन बांटने वाली ताक़तों को पहचान पाते हैं, जो कभी हमारे बीच फूट डालने की कोशिश करेंगी। चाहे वह सांप्रदायिकता हो, जातिवाद हो या किसी भी प्रकार की घृणा की राजनीति – हमें उसे पूरी शक्ति से नकारना होगा, क्योंकि हमने जान लिया है कि ऐसा ज़हर फलता-फूलता है तो पूरा देश जल उठता है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने इतिहास – उसके गौरव और उसके दर्द – दोनों का साहस के साथ सामना कर रहा है। यह ईमानदार आत्म-मंथन हमें और सबल बनाता है। यह हमारी एकता को और मजबूत सीमेंट की तरह जोड़ता है, क्योंकि जो राष्ट्र अपने सबसे बड़े दुःख को याद रखता है, वह अपनी वर्तमान एकता की रक्षा और भी चौकसी से करेगा।

आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने इतिहास – उसके गौरव और उसके दर्द – दोनों का साहस के साथ सामना कर रहा है। यह ईमानदार आत्म-मंथन हमें और सबल बनाता है। यह हमारी एकता को और मजबूत सीमेंट की तरह जोड़ता है, क्योंकि जो राष्ट्र अपने सबसे बड़े दुःख को याद रखता है, वह अपनी वर्तमान एकता की रक्षा और भी चौकसी से करेगा।

विभाजन को अब अठहत्तर वर्ष होने को आए। दुनिया काफ़ी बदल चुकी है, भारत ने फिर अपने को नई ऊंचाइयों पर स्थापित कर लिया है। और उस भीषण समय के कई प्रत्यक्षदर्शी अब इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन उनका कर्ज़ उतारना अभी बाक़ी है – उनकी कहानी सुनाना, उनके दुःख से सीखना अभी हमारा दायित्व है। हम यह दास्तान इसलिए बयां नहीं करते कि फिर से दिलों में कड़वाहट जागे – बिल्कुल नहीं। हम इसे इसलिए सुनाते हैं कि उनके धैर्य और जिजीविषा को सलाम कर सकें, और खुद को याद दिलाएं कि ऐसी फूट दोबारा हमारे राष्ट्र में कभी नहीं पड़ने देनी। इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर, जब देशभर में लोग मोमबत्तियां जलाकर, सायरन बजाकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, तब मेरी आंखों के आगे एक तस्वीर उभरती है: अमृतसर की एक वृद्धा अपने यादों के संदूक़ को धीरे से खोल रही है। उसमें पुराने कपड़ों और पीतल के बर्तनों के बीच रखी है उस घर की लोहे की चाबी, जिसे वह 1947 में पीछे छोड़ आई थी। वह कांपते हाथों से उसे उठाती है। चाबी ज़ंग खा चुकी है, छूने में ठंडी है, पर उस दादी अम्मा के लिए वह सोने से भी ज्यादा क़ीमती है। उस चाबी में दर्द और गौरव की मिश्रित कहानी बसी है: दर्द उस समूची दुनिया के उजड़ जाने का, गौरव इस बात का कि इतनी विषमता के बीच भी उन्होंने अपना आत्मसम्मान, अपना परिवार, अपनी आस नहीं छोड़ी। वह वृद्धा 1947 की त्रासदी से बच निकली और यह तय किया कि उसके बच्चे उस जैसा दुःख दोबारा ना झेलें। आज वह चाबी एक चेतावनी भी है और एक मशाल भी। चेतावनी इस बात की कि यदि नफ़रत का दानव हावी हो जाए तो घर-बार जलते देर नहीं लगती और राष्ट्र तक बिखर जाते हैं। और मशाल इस मायने में कि यादों और एकता का प्रकाश हमें भविष्य के अंधेरे रास्तों में दिशा दिखाता रहेगा – यह यक़ीन कि हम सब मिलकर सुनिश्चित करें कि दुश्मनी की वह आंधी फिर कभी न उठे जिसने किसी ज़माने में लाखों लोगों को ताले लगाकर सदा के लिए अपने घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। हमारे अतीत की ये चाबियां हमें आगाह करती हैं कि भारत के भविष्य को वैसा ज़ख़्म फिर न झेलना पड़े। ये प्रतीक हैं कि हमें अपना देश ऐसा बनाना है जहां फिर कोई मज़बूर न हो कि अपना घर-आंगन, अपनी मिट्टी को हमेशा के लिए अलविदा कहे। और यही इन चाबियों का सबक़ है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत सिर्फ नारा नहीं अपितु एकता एकजुटता का विजय मंत्र, राष्ट्र मंत्र है, हमारी नींव है और नफ़रत के अंधेरे का मुक़ाबला सिर्फ़ प्यार और मजबूत एकता के उजाले से किया जा सकता है और हमें हमेशा इसी रोशनी को थामे रखना है। ■

(लेखक भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

जो खेलता है, वो खिलता है: नरेन्द्र मोदी

'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना देश की एकता, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 31 अगस्त को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 125वीं कड़ी की शुरुआत करते हुए कहा कि मॉनसून के इस मौसम में प्राकृतिक आपदाएं देश की कसौटी कर रही हैं। पिछले कुछ हफ्तों में हमने बाढ़ और भू-स्खलन का बड़ा कहर देखा है। कहीं घर उजड़ गए, कहीं खेत डूब गए, परिवार के परिवार उजड़ गए, पानी के तेज बहाव में कहीं पुल बह गए, सड़कें बह गईं, लोगों का जीवन संकट में फंस गया। इन घटनाओं ने हर हिन्दुस्तानी को दुःखी किया है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजन खोए, उनका दर्द हम सबका दर्द है।

उन्होंने कहा कि जहां भी संकट आया, वहां के लोगों को बचाने के लिए हमारे एनडीआरएफ-एसडीआरएफ के जवान, अन्य सुरक्षा बल हर कोई दिन-रात जुटे रहे। जवानों ने तकनीक का सहारा भी लिया है। थर्मल कैमरे, लाइव डिटेक्टर, स्निफर डॉग्स और ड्रोन सर्विलांस ऐसे अनेक आधुनिक संसाधनों के सहारे राहत कार्य में तेजी लाने की भरपूर कोशिश की गई। इस दौरान हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री पहुंचाई गई, घायलों को एयरलिफ्ट किया गया। आपदा की घड़ी में सेना मददगार बनकर सामने आई। स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, डॉक्टर, प्रशासन, संकट की इस घड़ी में सभी ने हर संभव प्रयास किया। मैं ऐसे हर नागरिक को हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कठिन समय में मानवीयता को सबसे ऊपर रखा हुआ है।

देश में हुआ पहला 'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल'

श्री मोदी ने कहा कि बाढ़ और बारिश की इस तबाही के बीच जम्मू-कश्मीर ने दो बहुत खास उपलब्धियां भी हासिल की हैं। इन पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब आप उन उपलब्धियों के बारे में जानेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा के एक स्टेडियम में रिकॉर्ड संख्या में लोग इकट्ठा हुए। यहां पुलवामा का पहला डे-नाईट क्रिकेट मैच खेला गया। पहले ये होना असंभव था, लेकिन अब मेरा देश बदल रहा है।

उन्होंने कहा कि दूसरा आयोजन जिसने ध्यान खींचा, वो है देश में हुआ पहला 'खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल' और वो भी श्रीनगर की डल झील पर हुआ। सचमुच, ऐसा उत्सव आयोजित करने के लिए ये कितनी खास जगह है। इसका उद्देश्य है जम्मू-कश्मीर में वॉटर स्पोर्ट्स को और लोकप्रिय बनाना। इसमें पूरे भारत से 800 से अधिक एथलीटों ने हिस्सा लिया। महिला एथलीट भी पीछे नहीं रही उनकी भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर थी।

श्री मोदी ने कहा कि 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की भावना, देश की एकता, देश के विकास के लिए बहुत जरूरी है और निश्चित तौर पर खेल इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं और इसलिए ही तो मैं कहता हूं जो खेलता

है, वो खिलता है। हमारा देश भी जितने टूर्नामेंट खेलेगा, उतना खिलेगा।

प्रतिभा सेतु: होनहार विद्यार्थियों के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म

प्रधानमंत्री ने कहा कि आपने यूपीएससी का नाम तो जरूर सुना होगा। ये संस्था देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा की परीक्षा भी लेती है। हम सबने सिविल सेवा के टॉपर्स की प्रेरणादायी बातें अनेक बार सुनी हैं। ये नौजवान कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई के बाद अपनी मेहनत से इस सेवा में जगह पाते हैं, लेकिन यूपीएससी की परीक्षा की एक सच्चाई और भी है। हजारों ऐसे उम्मीदवार भी होते हैं, जो बेहद काबिल होते हैं, उनकी मेहनत भी किसी से कम नहीं होती, पर मामूली अंतर से वो अंतिम सूची तक नहीं पहुंच पाते। इन उम्मीदवारों को दूसरी परीक्षाओं के लिए नए सिरे से तैयारी करनी पड़ती है। इसमें उनका समय और पैसा दोनों खर्च होता था। इसलिए अब ऐसे होनहार विद्यार्थियों के लिए भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है और इसका नाम है 'प्रतिभा सेतु'।

श्री मोदी ने कहा कि 'प्रतिभा सेतु' में उन उम्मीदवारों का डाटा रखा गया है, जिन्होंने यूपीएससी की अलग-अलग परीक्षाओं के सभी चरण पास किए, लेकिन अंतिम मेरिट लिस्ट में उनका नाम नहीं आ पाया। इस पोर्टल पर दस हजार से ज्यादा ऐसे होनहार युवाओं का डाटाबैंक मौजूद है। कोई सिविल सेवा की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग सेवा में जाना चाहता था, कोई मेडिकल सेवा के हर पड़ाव को पार कर चुका था, लेकिन फाइनल में उसका चयन नहीं हुआ— ऐसे सभी उम्मीदवारों की जानकारी अब 'प्रतिभा सेतु' पोर्टल पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस पोर्टल से प्राइवेट कंपनियां इन होनहार छात्रों की जानकारी लेकर उन्हें अपने यहां नियुक्ति दे सकती हैं।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मुंबई में सुनी 'मन की बात'

मोदीजी के नेतृत्व में भारत 'आत्मनिर्भरता एवं विकास' के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा : जगत प्रकाश नड्डा

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 31 अगस्त, 2025 को मुंबई में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 125वीं कड़ी कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के साथ सुनी। इस अवसर पर पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री श्री विनोद तावड़े सहित अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।

गणेशोत्सव के पावन मौके पर श्री नड्डा ने मुंबई के चंद्रलोक गणपति मंडल में विराजे विघ्नहर्ता गणपति बप्पा के दर्शन किए। इसके उपरांत उन्होंने मंडप में उपस्थित लोगों के साथ 'मन की बात' का प्रसारण सुना। उन्होंने कहा कि यह क्षण उनके लिए विशेष है क्योंकि गणेशजी के सान्निध्य में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रेरक संदेशों को सुनने का अवसर मिला।

उन्होंने कहा कि 'मन की बात' केवल एक रेडियो कार्यक्रम नहीं, बल्कि यह जन-जन से संवाद का सेतु है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नागरिकों को 'विकसित भारत' और 'आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया है। प्रधानमंत्रीजी ने हमारी खेल प्रतिभाओं, वैज्ञानिक नवाचारों समेत दैनिक जीवन में स्वदेशी वस्तुओं के अधिकाधिक प्रयोग आदि के संबन्ध में अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए हैं। अब तक इस कार्यक्रम ने लाखों-करोड़ों लोगों को देशभक्ति, नवाचार और सामाजिक उत्थान की दिशा में कार्य करने की प्रेरणा दी है।

श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देशभर में हो रहे विभिन्न नवाचारों को एक पटल पर लाकर लोगों को प्रेरित किया। उनकी दूरदर्शी सोच और निरंतर संवाद ने देशभर में लोगों को एकजुट किया है। श्री नड्डा ने विश्वास जताया कि मोदीजी के नेतृत्व में भारत आत्मनिर्भरता और विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा।

इसके पश्चात् श्री नड्डा ने लालबागचा राजा के दर्शन किये। उन्होंने कामना की कि विघ्नहर्ता भगवान गणेश सभी के जीवन से विघ्न दूर करें और सुख-समृद्धि व मंगल का आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फड़णवीसजी के घर पर भगवान् गणपति के दर्शन किये और पूजन-अर्चन किया। साथ ही, उन्होंने महाराष्ट्र राजभवन में विराजे भगवान गजानन के दर्शन किये और राज्यपाल एवं एनडीए उप-राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री सी.पी. राधाकृष्णनजी से भी शिष्टाचार भेंट की। ■

उन्होंने कहा कि इस प्रयास के नतीजे भी आने लगे हैं। सैकड़ों उम्मीदवारों को इस पोर्टल की मदद से तुरंत नौकरी मिली है और वो युवा जो मामूली अंतर से रुक गए थे, अब नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं।

श्री मोदी ने कहा कि आजकल आपने देखा होगा, अक्सर घर की छतों पर, बड़ी इमारतों पर, सरकारी दफ्तरों में सौर पेनल चमकते हुए दिखाई देते हैं। लोग अब इसके महत्व को समझ रहे हैं और खुले मन से अपना रहे हैं। हमारे देश पर सूर्यदेव की इतनी कृपा है, तो क्यों न उनकी दी हुई उस ऊर्जा का पूरा उपयोग करें।

भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी

श्री मोदी ने कहा कि 15 सितंबर को भारत के महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्मदिन होता है। उस दिन को हम 'इंजीनियर्स डे' के रूप में मनाते हैं। इंजीनियर सिर्फ मशीन नहीं बनाते, वे सपनों को हकीकत में बदल देने वाले कर्मयोगी होते हैं। मैं भारत के हर इंजीनियर की सराहना करता हूं। उन्हें अपनी शुभकामनाएं देता हूं।

उन्होंने कहा कि सितंबर में ही भगवान विश्वकर्मा की पूजा का पवित्र अवसर भी आने वाला है। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती है। ये दिन हमारे उन विश्वकर्मा बंधुओं को भी समर्पित है, जो पारंपरिक शिल्प, कौशल और ज्ञान-विज्ञान को अनवरत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। हमारे सुतार, लोहार, सोनार, कुम्हार, मूर्तिकार, बढ़ई-मिस्त्री हमेशा से भारत की समृद्धि की बुनियाद रहे हैं। हमारे इन विश्वकर्मा बंधुओं की मदद के लिए ही सरकार ने विश्वकर्मा योजना भी चलाई है।

सितंबर महीने में हम मनाएंगे 'हैदराबाद मुक्ति दिवस'

श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने सितंबर में हम हैदराबाद मुक्ति दिवस भी मनाएंगे। ये वही महीना है जब हम उन सभी वीरों के साहस को याद करते हैं जिन्होंने 'ऑपरेशन पोलो' में हिस्सा लिया था। आप सबको मालूम है कि जब अगस्त, 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो हैदराबाद अलग ही स्थिति में था। निज़ाम और रज़ाकारों के अत्याचार दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे थे। तिरंगा फहराने या 'वंदे मातरम्' कहने पर भी मौत के घाट उतार दिया जाता था। महिलाओं और गरीबों पर अत्याचार किए जाते थे।

उन्होंने कहा कि उस समय बाबा साहेब अंबेडकर ने भी चेतावनी दी थी कि ये समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। आखिरकार, सरदार पटेल ने मामले को अपने हाथ में लिया। उन्होंने सरकार को 'ऑपरेशन पोलो' शुरू करने के लिए तैयार किया। रिकॉर्ड समय में हमारी सेनाओं ने हैदराबाद को निज़ाम की तानाशाही से आज़ाद कराया और उसे भारत का हिस्सा बनाया। पूरे देश ने इस सफलता का उत्सव मनाया। ■

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री से भेंट की

'भाजपा को जानें' पहल के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने 03 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली में सिंगापुर के प्रधानमंत्री महामहिम श्री लॉरेंस वोंग से भेंट की।

प्रधानमंत्री श्री वोंग का स्वागत करते हुए श्री नड्डा ने इस यात्रा के विशेष महत्व पर प्रकाश डाला, जोकि यह भारत-सिंगापुर राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ के अवसर पर हो रही है।

श्री नड्डा ने भाजपा को जानें पहल के तहत भारतीय जनता पार्टी की व्यापक संगठनात्मक पहुंच पर प्रकाश डाला और सिंगापुर की पीपुल्स एक्शन पार्टी के साथ बेहतर सहयोग का प्रस्ताव रखा।

श्री वोंग ने भाजपा के निमंत्रण पर अपनी पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल की भारत यात्रा का ज़िक्र किया और बताया कि इस यात्रा से भाजपा की कार्यप्रणाली के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिली। दोनों नेताओं ने भविष्य में भी पार्टी प्रतिनिधिमंडलों के आदान-प्रदान को जारी रखने पर सहमति जताई।

श्री नड्डा ने स्वास्थ्य सेवा सहयोग पर 2024 के समझौता ज्ञापन के महत्व को भी रेखांकित किया और भारत के स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में टेमासेक के निवेश का स्वागत किया, जो भारत के स्वास्थ्य सेवा पारिस्थितिकी तंत्र में वैश्विक विश्वास को दर्शाता है। दोनों नेताओं ने निवारक स्वास्थ्य सेवा के महत्व और इसमें प्रौद्योगिकी की भूमिका पर ज़ोर दिया। दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स में सहयोग को गहरा करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जिससे भारत-सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी और मज़बूत होगी।

इस बैठक में श्री नड्डा के साथ भाजपा के विदेश मामलों के विभाग के प्रभारी डॉ. विजय चौथाईवाले भी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री महामहिम श्री वोंग भारत की राजकीय यात्रा पर थे। सिंगापुर के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक भारत यात्रा थी। ■

पृष्ठ १९ का शेष भाग...

हैं और गरीब परिवारों के लिए छोटी लेकिन सार्थक वास्तविक आय वृद्धि प्रदान करते हैं, जो व्यापक कल्याण और समावेशन उद्देश्यों के अनुरूप है।

दीर्घकालिक संरचनात्मक लाभ

सरलीकृत दरें अनुपालन को बढ़ा सकती हैं, जिससे समय के साथ कर योग्य आधार का विस्तार हो सकता है। अधिक औपचारिकता तत्काल राजस्व हानि की कुछ हद तक भरपाई कर सकती है। इनवर्टेड ड्यूटी को हटाने और इनपुट करों को कम करने से विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से वस्त्र और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों में, जिससे मध्यम अवधि में निर्यात की संभावनाओं में सुधार होगा। मुख्य खाद्य पदार्थों और घरेलू सामानों की लगातार कम कीमतें गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाती हैं, जिससे वास्तविक आय में सुधार होता है और उपभोग में संतुलन बना रहता है, जो बदले में मानव विकास संकेतकों को बढ़ावा देता है। टिकाऊ और अर्ध-टिकाऊ वस्तुओं की बढ़ती खपत कंपनियों को निवेश करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जिससे रोजगार और उत्पादकता में वृद्धि होगी। विश्लेषकों की टिप्पणी वित्त वर्ष 27 में विकास में तेजी की संभावना पर प्रकाश डालती है।

2025 का जीएसटी सुधार एक ऐतिहासिक कदम है जो परिवारों के लिए दृश्यमान कल्याणकारी लाभों को दीर्घकालिक औद्योगिक और प्रतिस्पर्धात्मकता लाभों के साथ जोड़ती है। तत्काल राजस्व प्रभाव और निरंतर वृद्धि के बीच का संतुलन कार्यान्वयन की गुणवत्ता और औपचारिकता के लाभ की प्राप्ति की सीमा से हल हो जाएगा। उद्योग जगत की शुरुआती प्रतिक्रियाएं और आधिकारिक दस्तावेज़ सकारात्मक परिणामों और वैध राजकोषीय प्रश्नों, दोनों का संकेत देते हैं जिनका नीति निर्माताओं को विवेकपूर्ण ढंग से प्रबंधन करना चाहिए।

यह साहसिक कदम कल्याण और विकास, सरलता और दक्षता तथा उपभोग और प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाने के मोदी सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। उद्योग जगत में संरचनात्मक विकृतियों को दूर करते हुए आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती करके यह सुधार लाखों परिवारों को राहत प्रदान करता है और भारतीय उद्यमों को वैश्विक बाज़ारों में एक मज़बूत बढ़त प्रदान करता है। यह एक निर्णायक संकेत है कि प्रधानमंत्री मोदीजी के नेतृत्व में राजकोषीय नीति केवल राजस्व संग्रह तक ही सीमित नहीं है, बल्कि नागरिकों को सशक्त बनाने, उद्योग को प्रोत्साहित करने और भारत के दीर्घकालिक विकास पथ को मज़बूत करने के लिए भी है। ■

(लेखक राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री हैं)

तियानजिन (चीन) में 01 सितंबर, 2025 को आयोजित एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान एक समूह चित्र में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

तियानजिन (चीन) में 31 अगस्त, 2025 को चीन के राष्ट्रपति श्री शी जिनपिंग से भेंट करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

तियानजिन (चीन) में 01 सितंबर, 2025 को रूस के राष्ट्रपति श्री व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करते प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

टोक्यो (जापान) में 29 अगस्त, 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का स्वागत करते जापान के प्रधानमंत्री श्री शिगेरु इशिबा

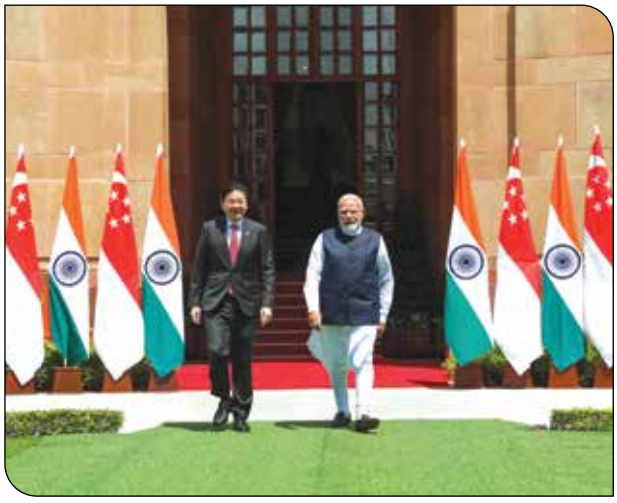

हैदराबाद हाउस (नई दिल्ली) में 04 सितंबर, 2025 को सिंगापुर के प्रधानमंत्री श्री लॉरेंस वोंग और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

कमल संदेश
अब इंटरनेट पर भी उपलब्ध
लॉग इन करें:
www.kamalsandesh.org
राष्ट्रीय विचार की प्रतिनिधि पाक्षिक पत्रिका

@Kamal.Sandesh
@KamalSandesh
kamal.sandesh
KamalSandeshLive

डाकघर: लोदी रोड एचओ., नई दिल्ली "रजिस्टर्ड"
36 पृष्ठ कवर सहित
प्रकाशन तिथि: 20 सितम्बर, 2025
आर.एन.आई. DELHIN/2006/16953

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025
'विकसित भारत' की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

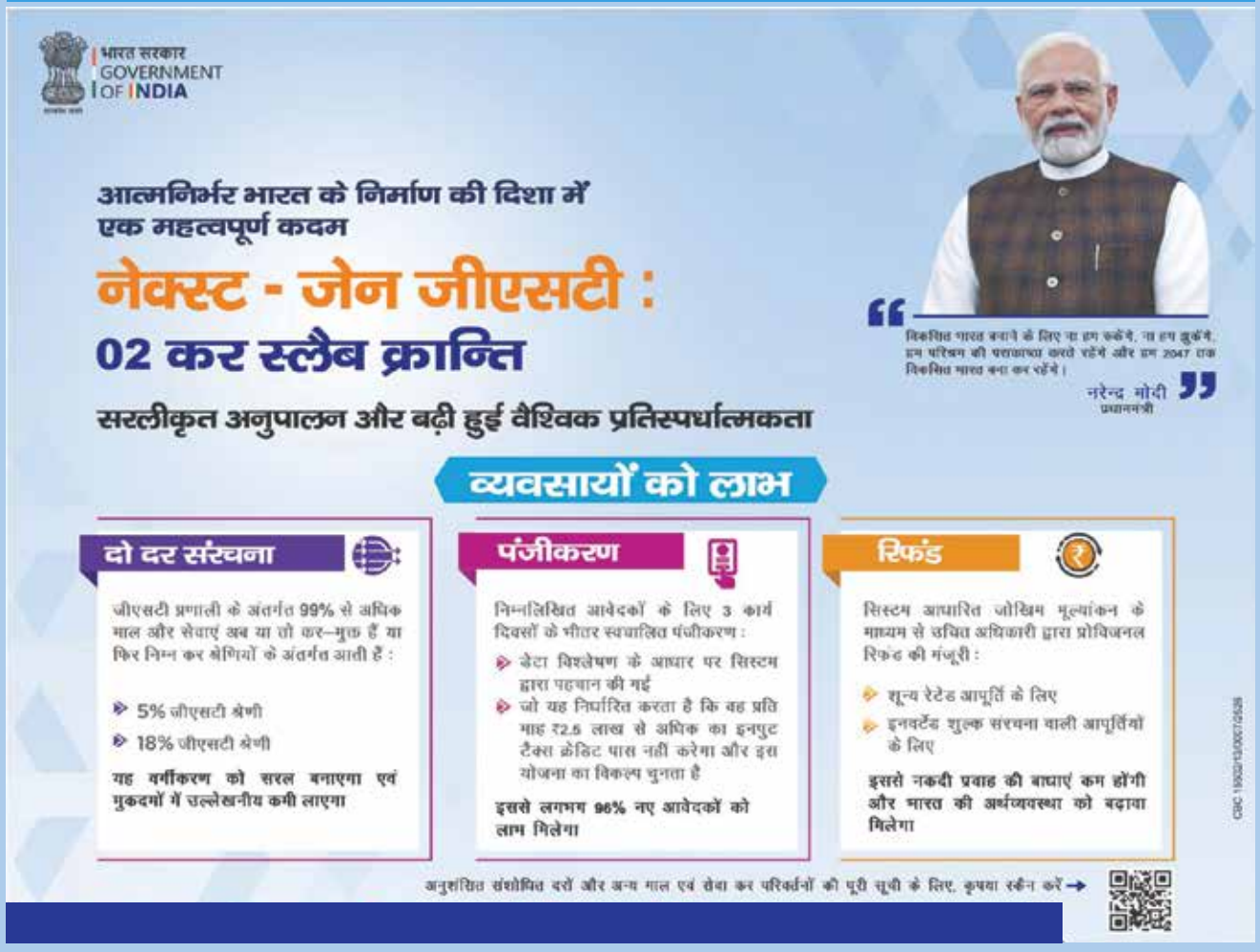

छायाकार: अजय कुमार सिंह